

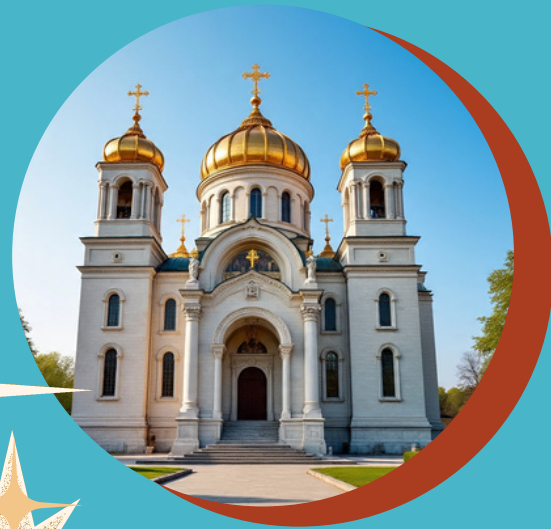


Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam



NOVEMBER MONTH BANKING AND FINANCIAL AWARENESS



120+ MCQ
with detailed
explanation

- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement



Ques: Which Kolkata-based microfinance institution withdrew its application under the RBI's 'on tap' licensing guidelines for small finance banks?

कौन सा कोलकाता स्थित माइक्रोफाइनेंस संस्थान RBI के 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग गाइडलाइंस के तहत आवेदन वापस ले चुका है?

- A) VFS Capital Ltd / वीएफएस कैपिटल लिमिटेड
- B) Ujjivan Small Finance Bank / उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
- C) Bandhan Bank / बंधन बैंक
- D) Equitas Small Finance Bank / इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक
- E) ESAF Small Finance Bank / ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या :

- The Reserve Bank of India stated that VFS Capital Ltd, a Kolkata-based microfinance institution, has withdrawn its application submitted under the guidelines for 'on tap' licensing of small finance banks.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि कोलकाता स्थित माइक्रोफाइनेंस संस्था VFS Capital Ltd ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग गाइडलाइंस के तहत अपना आवेदन वापस ले लिया है।
- VFS Capital was among the 72 applicants who had applied for a small finance bank license a decade ago, when RBI first proposed the concept of differentiated banks.
- VFS Capital उन 72 आवेदकों में से एक था जिन्होंने दस साल पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जब RBI ने पहली बार भिन्नीकृत बैंकों (differentiated banks) की अवधारणा प्रस्तावित की थी।
- The RBI had earlier announced receipt of VFS Capital's application in its press release dated January 1, 2025.
- RBI ने 1 जनवरी 2025 को अपनी प्रेस रिलीज़ में VFS Capital के आवेदन की प्राप्ति की जानकारी पहले ही दी थी।

Ques: Who has been appointed as the part-time chairman of Kotak Mahindra Bank starting January 1, 2026?

किसे 1 जनवरी 2026 से Kotak Mahindra Bank का पार्टचेयर टाइम-मैन नियुक्त किया गया है?

- A) Uday Kotak / उदय कोटक
- B) Chandra Shekhar (C S) Rajan / चंद्र शेखर राजन (एस सी)
- C) Ashok Vaswani / अशोक वासवानी
- D) Rakesh Jhunjhunwala / राकेश झुनझुनवाला
- E) Aditya Puri / आदित्य पुरी

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या :

- Veteran bureaucrat Chandra Shekhar (C S) Rajan has been appointed as the part-time chairman of Kotak Mahindra Bank, with his term starting on January 1, 2026 and ending on October 21, 2027.
- अनुभवी नौकरशाह चंद्र शेखर को राजन (एस सी) Kotak Mahindra Bank का पार्टचेयर टाइम-मैन नियुक्त किया गया, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 21 अक्टूबर 2027 तक रहेगा।
- Rajan has been serving in this role since January 1, 2024, providing continuity and experience to the bank's leadership.
- राजन 1 जनवरी 2024 से इस भूमिका में कार्यरत हैं, जिससे बैंक के नेतृत्व में निरंतरता और अनुभव सुनिश्चित होता है।
- About Kotak Mahindra Bank: Established on November 21, 1985, headquartered in Mumbai, with Ashok Vaswani as CEO.
- Kotak Mahindra Bank की स्थापना 21 नवंबर 1985 को हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है और अशोक वासवानी CEO हैं।

Ques: The World Bank approved a loan of how much amount to Kerala under the Kerala Health System Improvement Programme to enhance the state's healthcare system?

विश्व बैंक ने केरल के स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के तहत राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कितनी राशि का ऋण मंजूर किया है?

- A) USD 150 million
- B) USD 200 million
- C) USD 250 million
- D) USD 280 million
- E) USD 300 million

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या :

- The World Bank approved a USD 280 million loan to Kerala under the Kerala Health System Improvement Programme to strengthen the state's healthcare infrastructure.
- विश्व बैंक ने केरल हेल्थ सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत केरल की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 280 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है।
- The loan is provided through the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) with a maturity period of 25 years and a 5-year grace period.
- यह ऋण अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) द्वारा 25 वर्ष की परिपक्वता अवधि और 5 वर्ष की अनुग्रह अवधि के साथ प्रदान किया गया है।
- Funding follows the Programme for Results (PforR) model, ensuring disbursement only after achieving measurable outcomes.
- फंडिंग प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स (PforR) मॉडल के तहत की जाएगी, जिसमें केवल निर्धारित परिणाम प्राप्त होने पर ही धनराशि जारी की जाएगी।
- The initiative focuses on controlling hypertension and diabetes, targeting 90% coverage of registered patients using digital tracking systems.
- यह पहल हाइपरटेंशन और डायबिटीज नियंत्रण पर केंद्रित है, जिसमें पंजीकृत मरीजों के 90% कवरेज और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के उपयोग का लक्ष्य रखा गया है।
- It also aims to provide comprehensive healthcare for bedridden, homebound, and elderly individuals through medical check-ups, nursing support, and preventive care.
- यह योजना विस्तर पर पड़े, घर पर रहने वाले और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे मेडिकल चेकअप, नर्सिंग सहायता और निवारक देखभाल प्रदान करेगी।
- The programme targets a 40% improvement in hypertension control and a

60% rise in cervical and breast cancer screenings to reduce preventable deaths.

- इस कार्यक्रम का लक्ष्य हाइपरटेंशन नियंत्रण में 40% सुधार और सर्वाइकल व ब्रेस्ट कैंसर की जांच में 60% वृद्धि करके रोके जा सकने वाली मौतों को कम करना है।

Ques: Which lending arm of the World Bank provided a loan of ₹875 crore to Signature Global?

किस वर्ल्ड बैंक की लेंडिंग शाखा ने सिग्नेचर ग्लोबल को ₹875 करोड़ का ऋण दिया?

- A) Asian Development Bank / एशियन डेवलपमेंट बैंक
- B) IFC (International Finance Corporation) / IFC (इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन)
- C) IMF Lending Arm / IMF की लेंडिंग शाखा
- D) World Bank IBRD / वर्ल्ड बैंक IBRD
- E) ADB & IFC Joint / ADB और IFC संयुक्त रूप से

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The International Finance Corporation (IFC), the private-sector lending arm of the World Bank Group, provided ₹875 crore to Signature Global via a private placement of non-convertible debentures (NCDs).
- वर्ल्ड बैंक समूह की निजी) क्षेत्र लेंडिंग शाखा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन-IFC) ने सिग्नेचर ग्लोबल को ₹875 करोड़ का ऋण (नॉन) कन्वर्टिबल डिबेंचर्स-NCDs) के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से दिया।
- The NCDs are rated A+ (Stable), carry an 11% coupon rate, and will mature on 15 January 2029.
- इन NCDs को A+ (Stable) रेटिंग मिली है, इनकी कूपन दर 11% है और परिपक्वता तिथि 15 जनवरी 2029 है।
- About 55% of the proceeds (~₹470 crore) will retire existing debt, while the remainder will fund mid-income housing and ESG-aligned projects.
- कुल राशि का लगभग 55% (~₹470 करोड़) मौजूदा ऋण चुकाने के लिए उपयोग किया (इनकम हाउसिंग व-जाएगा और बाकी मिड-ESG-अनुरूप परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा।

Ques: What is the rate of interest on Government of India Floating Rate Bond 2034 (GOI FRB 2034) for the half-year October 30, 2025, to April 29, 2026?
30 अक्टूबर 2025 से 29 अप्रैल 2026 तक के लिए भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034 (GOI FRB 2034) पर ब्याज की दर क्या है?

- A) 6.25% per annum
- B) 6.54% per annum
- C) 6.75% per annum
- D) 6.99% per annum
- E) 7.25% per annum

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The interest rate on GOI FRB 2034 for the half-year from October 30, 2025, to April 29, 2026, is fixed at 6.54% per annum.
- 30 अक्टूबर 2025 से 29 अप्रैल 2026 तक के लिए GOI FRB 2034 की ब्याज दर 6.54% वार्षिक निर्धारित की गई है।
- The coupon has a base rate equal to the average Weighted Average Yield (WAY) of the last three 182-day T-Bill auctions from the rate fixing day, plus a fixed spread of 0.98%.
- इस बॉन्ड का कूपन बेस दर पिछले तीन 182-दिन के T-Bill नीलामी का औसत WAY (Rate Fixing Day से और 0.98% का स्थिर स्प्रेड जोड़कर निर्धारित किया जाता है।
- For the previous half-year (April 30, 2025, to October 29, 2025), the interest rate was 6.99% per annum.
- पिछली अर्धवार्षिक अवधि (30 अप्रैल 2025 से 29 अक्टूबर 2025) के लिए ब्याज दर 6.99% वार्षिक थी।

Ques: Which company partnered with OpenAI to enable a digital wallet in ChatGPT, allowing users to purchase goods and services directly through the AI chatbot?

कौन सी कंपनी ने OpenAI के साथ साझेदारी की है ताकि ChatGPT में डिजिटल वॉलेट सक्षम हो सके, जिससे उपयोगकर्ता सीधे AI चैटबॉट के माध्यम से वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें?

- A) Google Pay / गूगल पे

- B) PhonePe / फोनपे
- C) Apple Pay / एप्पल पे
- D) Amazon Pay / अमेज़न पे
- E) PayPal / पेपैल

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- PayPal partnered with OpenAI to enable a digital wallet in ChatGPT, allowing users to purchase goods and services directly through the AI chatbot.
 - पेपैल ने OpenAI के साथ साझेदारी की है ताकि ChatGPT में डिजिटल वॉलेट सक्षम हो सके, जिससे उपयोगकर्ता सीधे AI चैटबॉट के माध्यम से वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें।
 - With this collaboration, PayPal became the first digital wallet to be integrated into the AI chatbot.
 - इस साझेदारी के साथ, पेपैल पहला डिजिटल वॉलेट बन गया जो AI चैटबॉट में एकीकृत किया गया।
 - This move aligns with OpenAI's expansion into "Agent Mode," where ChatGPT can take automated actions such as purchasing or booking on user commands.
 - यह कदम OpenAI के "एजेंट मोड" के विस्तार के अनुरूप है, जिसमें ChatGPT उपयोगकर्ता के आदेशों पर स्वचालित कार्य जैसे खरीदारी या बुकिंग कर सकता है।
-

Ques: Which Small Finance Bank's application was returned by RBI for conversion into a Universal Bank?

किस स्मॉल फाइनेंस बैंक का यूनिवर्सल बैंक में रूपांतरण का आवेदन RBI ने लौटा दिया?

- A) AU Small Finance Bank / एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
- B) Fino Payments Bank / फिनो पेमेंट्स बैंक
- C) Jana Small Finance Bank / जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक
- D) Ujjivan Small Finance Bank / उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
- E) Equitas Small Finance Bank / इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) returned the application of Jana Small Finance Bank for conversion into a Universal Bank, citing non-fulfilment of eligibility criteria under RBI guidelines.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का यूनिवर्सल बैंक में रूपांतरण का आवेदन लौटा दिया क्योंकि बैंक RBI के दिशानिर्देशों में बताए गए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर सका।
- Eligibility criteria for SFBs include minimum 5 years of operations, listing on a recognised stock exchange, net worth of at least ₹1,000 crore, net profit in the last 2 financial years, and GNPA $\leq 3\%$ & NNPA $\leq 1\%$.
- SFBs के लिए पात्रता शर्तों में कम से कम 5 वर्षों का संचालन, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना, न्यूनतम ₹1,000 करोड़ की निवल संपत्ति, पिछले 2 वर्षों में शुद्ध लाभ, और GNPA $\leq 3\%$ व NNPA $\leq 1\%$ शामिल हैं।
- RBI also stated that eligible SFBs with diversified loan portfolios will be preferred for Universal Bank licensing.
- RBI ने यह भी कहा कि विविधीकृत ऋण पोर्टफोलियो वाले पात्र SFBs को यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

Ques: Which bank won the “BFSI Brand of the Year” at the FINIXX Summit & Awards 2025?

किस बैंक को मुंबई में आयोजित FINIXX Summit & Awards 2025 में “BFSI Brand of the Year” पुरस्कार मिला?

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) State Bank of India (SBI) / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) won multiple awards at the FINIXX Summit & Awards 2025, including “BFSI Brand of the Year,” “Best Use of AI/ML in Marketing (Banking Sector),” and “Best Use of Video Marketing (Banking Sector).”
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने FINIXX Summit & Awards 2025 में “BFSI Brand of the Year,” “Best Use of AI/ML in Marketing (Banking Sector),” और “Best Use of Video Marketing (Banking Sector)” सहित कई पुरस्कार जीते।
- The awards were organized by Adgully Network Pvt. Ltd. in Mumbai under the theme “Reimagining BFSI: Powering Digital Bharat Goals.”
- ये पुरस्कार मुंबई में Adgully Network Pvt. Ltd. द्वारा “Reimagining BFSI: Powering Digital Bharat Goals” थीम के तहत आयोजित किए गए।

Ques: Which company has enabled Unified Payments Interface (UPI) payments for Non-Resident Indians (NRIs) through their international mobile numbers?

किस कंपनी ने प्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए उनके अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भुगतान सक्षम किया है?

- A) PhonePe / फोनपे
- B) Google Pay / गूगल पे
- C) BharatPe / भारतपे
- D) Amazon Pay / अमेज़न पे
- E) Paytm / पेटीएम

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Paytm has enabled Unified Payments Interface (UPI) payments for Non-Resident Individuals (NRIs) through their international mobile numbers.
- पेटीएम ने प्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए उनके अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भुगतान की सुविधा शुरू की है।
- Currently, the facility is available in beta mode and will be rolled out

gradually to all eligible users.

- वर्तमान में यह सुविधा बीटा मोड में उपलब्ध है और धीरेधीरे सभी पात्र उपयोगकर्ताओं - के लिए शुरू की जाएगी।

- The service, powered by the National Payments Corporation of India (NPCI), is available to Indians in 12 countries including Singapore, Australia, Canada, Hong Kong, Oman, Qatar, USA, Saudi Arabia, UAE, UK, France, and Malaysia.

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा समर्थित यह सेवा 12 देशों — सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), यूनाइटेड किंगडम (UK), फ्रांस और मलेशिया — में रहने वाले भारतीयों के लिए उपलब्ध है।

Ques: Which Japanese fintech firm launched “JPYC,” the world’s first Yen-pegged stablecoin?

कौन सी जापानी फिनटेक कंपनी ने “JPYC” लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला येनपेग्ड - स्थिर कॉइन है?

A) JPYC Inc. / JPYC इंक.

B) Mitsubishi UFJ Financial / मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल

C) Sony Financial / सोनी फाइनेंशियल

D) SoftBank Vision Fund / सॉफ्टबैंक विज़न फंड

E) Rakuten Pay / राकुटेन पे

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Japanese fintech firm JPYC Inc. launched “JPYC,” the world’s first Yen-pegged stablecoin, which is pegged equal in value to the Japanese Yen.

- जापानी फिनटेक कंपनी JPYC Inc. ने “JPYC” लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला येनपेग्ड - स्थिर कॉइन है और जिसकी मूल्यांकन जापानी येन के बराबर है।

- The coin operates on multiple blockchains, including Ethereum, Avalanche, and Polygon, enabling wallets, exchanges, and DeFi platforms to integrate JPYC and use it across different ecosystems.

- यह कॉइन कई ब्लॉकचेन पर कार्य करता है, जिनमें Ethereum, Avalanche और Polygon शामिल हैं, जिससे वॉलेट्स, एक्सचेंज और DeFi प्लेटफॉर्म JPYC को विभिन्न

इकोसिस्टम में एकीकृत और उपयोग कर सकते हैं।

- Users or partner institutions send JPY to the official account or “on-ramp,” a payment channel, and JPYC mints the same amount of JPYC tokens on the blockchain.
- उपयोगकर्ता या भागीदार संस्थान आधिकारिक खाते या “ऑनरैंप-” (भुगतान चैनल में (JPY भेजेंगे, और JPYC ब्लॉकचेन पर समान मात्रा में JPYC टोकन मिनट करेगा।

Ques: How much gold has the Reserve Bank of India repatriated in the half-year ending September 2025?

सितंबर 2025 तक समाप्त होने वाली अर्धवार्षिक अवधि में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कितने टन सोना देश वापस लाया है?

- A) 54 tonnes
- B) 64 tonnes
- C) 74 tonnes
- D) 84 tonnes
- E) 94 tonnes

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The RBI repatriated nearly 64 tonnes of gold in the half-year to September 2025 amid global concerns over offshore sovereign asset safety.
- वैश्विक स्तर पर विदेशों में रखे गए सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंता के बीच, RBI ने सितंबर 2025 तक की अर्धवार्षिक अवधि में लगभग 64 टन सोना देश वापस लाया।
- As of September-end 2025, RBI held 880.8 tonnes of gold: 575.8 tonnes in India, 290.3 tonnes with the Bank of England and BIS, and 14 tonnes as deposits.
- सितंबर 2025 के अंत तक, RBI के पास कुल 880.8 टन सोना था :575.8 टन भारत में, 290.3 टन बैंक ऑफ़ इंग्लैंड और BIS में, और 14 टन जमा के रूप में।
- Since March 2023, a total of 274 tonnes of gold have been repatriated due to geopolitical risks like the Russia–Ukraine war and Taliban takeover of Afghanistan.
- मार्च 2023 से, रूस-यूक्रेन युद्ध और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे जैसे भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण कुल 274 टन सोना देश वापस लाया गया है।

Ques: Which financial institution provided a USD 460 million loan along with a USD 40 million concessional loan from the Clean Technology Fund (CTF) for the Maharashtra Power Distribution Enhancement Program for Agricultural Solarization?

महाराष्ट्र पावर डिस्ट्रीब्यूशन एनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चरल सोलराइजेशन के लिए क्लीन टेक्नोलॉजी फंड (CTF) से USD 40 मिलियन और कुल USD 460 मिलियन का ऋण किस वित्तीय संस्थान ने प्रदान किया?

- A) World Bank / वर्ल्ड बैंक
- B) International Finance Corporation (IFC) / इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन
- C) Asian Development Bank (ADB) / एशियन डेवलपमेंट बैंक
- D) New Development Bank (NDB) / न्यू डेवलपमेंट बैंक
- E) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) / एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) provided a USD 460 million loan along with a USD 40 million concessional loan from the Clean Technology Fund (CTF) for the Maharashtra Power Distribution Enhancement Program aimed at Agricultural Solarization.
 - एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने महाराष्ट्र पावर डिस्ट्रीब्यूशन एनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चरल सोलराइजेशन के लिए क्लीन टेक्नोलॉजी फंड (CTF) से USD 40 मिलियन और कुल USD 460 मिलियन का ऋण प्रदान किया।
 - The program focuses on strengthening the agricultural electricity infrastructure and promoting solarization of farms in Maharashtra.
 - यह प्रोग्राम महाराष्ट्र में कृषि बिजली अवसंरचना को मजबूत करने और खेतों में सोलराइजेशन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
-

Ques: Who is the chairperson of the UIDAI expert panel formed to develop the 'Aadhaar Vision 2032'?

'आधार विज़न 2032' तैयार करने के लिए गठित यूआईडीएआई विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन हैं?

- A) Ajay Bhushan Pandey / अजय भूषण पांडे

- B) Neelkanth Mishra / नीलकंठ मिश्रा
- C) Saurabh Garg / सौरभ गर्ग
- D) Rajeev Chandrasekhar / राजीव चंद्रशेखर
- E) Girish Chandra Murmu / गिरीश चंद्र मूर्मू

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The UIDAI has constituted a high-level expert panel to develop the 'Aadhaar Vision 2032' framework, aiming to make India's digital identity ecosystem future-ready.
- यूआईडीएआई ने 'आधार विज़न 2032' ढांचा तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की है, जिसका उद्देश्य भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को भविष्य के अनुरूप बनाना है।
- Neelkanth Mishra serves as the chairperson of this panel, leading efforts to align Aadhaar's next-generation architecture with the DPDP Act and global cybersecurity standards.
- इस समिति के अध्यक्ष नीलकंठ मिश्रा हैं, जो आधार की अगली पीढ़ी की संरचना को डीपीडीपी अधिनियम और वैश्विक साइबर सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं।
- The initiative focuses on enhancing scalability, resilience, and security of Aadhaar against evolving cyber threats.
- इस पहल का उद्देश्य बदलते साइबर खतरों के खिलाफ आधार की विस्तारण क्षमता, लचीलापन और सुरक्षा को मजबूत करना है।

Ques: As of June 30, 2025, how many Prepaid Payment Instrument (PPI) cards were in circulation according to the Reserve Bank of India?

30 जून 2025 तक, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार कितनी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) कार्ड्स प्रचलन में थीं?

- A) 436 million
- B) 483 million
- C) 338 million
- D) 868 million

E) 890 million

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- As per RBI data, the total number of Prepaid Payment Instrument (PPI) cards increased 10.7% over six months to reach 483 million as of June 30, 2025, up from 436 million.
 - RBI के आंकड़ों के अनुसार, PPI कार्ड्स की कुल संख्या छह महीनों में 10.7% बढ़कर 30 जून 2025 तक 483 मिलियन हो गई, जो पहले 436 मिलियन थी।
 - The number of active PPI cards rose nearly fourfold to 338 million, showing strong user engagement and reactivation.
 - सक्रिय PPI कार्ड्स की संख्या लगभग चार गुना बढ़कर 338 मिलियन हो गई, जो उपयोगकर्ताओं में मजबूत पुनः सक्रियण प्रवृत्ति को दर्शाती है।
 - Meanwhile, PPI wallets declined slightly to 868 million from 890 million, indicating a preference shift from wallets to cards.
 - इसी बीच, PPI वॉलेट्स की संख्या 890 मिलियन से घटकर 868 मिलियन हो गई, जिससे वॉलेट्स से कार्ड्स की ओर झुकाव दिखता है।
-

Ques: According to RBI, which two countries together accounted for one-third of India's FDI during FY25?

RBI के अनुसार, FY25 के दौरान भारत के एक तिहाई-FDI के लिए कौन से दो देश जिम्मेदार थे?

- A) Japan and UAE / जापान और यूएई
- B) US and Singapore / अमेरिका और सिंगापुर
- C) UK and Mauritius / यूके और मॉरीशस
- D) France and Germany / फ्रांस और जर्मनी
- E) China and South Korea / चीन और दक्षिण कोरिया

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- According to the Reserve Bank of India (RBI), the United States and Singapore together contributed over one-third of India's total Foreign Direct Investment (FDI) during FY2024–25.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, अमेरिका और सिंगापुर ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का एकतिहाई से अधिक हिस्सा - योगदान दिया।
- The data was derived from RBI's census on foreign liabilities and assets of Indian direct investment entities, covering 41,517 entities reporting FDI and/or ODI in their balance sheets as of March 2025.
- यह आंकड़ा भारतीय प्रत्यक्ष निवेश संस्थाओं की विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों पर RBI की जनगणना से लिया गया, जिसमें मार्च 2025 तक 41,517 संस्थाओं ने अपनी बैलेंस शीट में FDI और या/ODI दर्ज किया।
- The report highlights the continued dominance of US and Singapore as major sources of FDI inflows into India.
- यह रिपोर्ट दर्शाती है कि अमेरिका और सिंगापुर भारत में FDI प्रवाह के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं।

Ques: Who has been appointed as the Deputy Managing Director (DMD) of HDFC Bank for a term starting from 13 October 2025?

किसे HDFC बैंक का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर (DMD) नियुक्त किया गया है, जिसकी अवधि 13 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी?

- A) Sashidhar Jagdishan / सशिधर जगदीशन
- B) Kaizad Bharucha / कैज़ाद भारुचा
- C) Aditya Puri / आदित्य पुरी
- D) Uday Kotak / उदय कोटक
- E) Rajnish Kumar / रजनीश कुमार

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Kaizad Bharucha has been appointed as Deputy Managing Director (DMD) of HDFC Bank for a tenure of 3 years, effective from 13 October 2025 to 12

October 2028.

- कैज़ाद भारुचा को HDFC बैंक का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर (DMD) नियुक्त किया गया है, जिसकी अवधि 13 अक्टूबर 2025 से 12 अक्टूबर 2028 तक 3 साल की है।
- He was earlier reappointed as DMD in 2022, and his previous term concluded in October 2025.
- उन्हें पहले 2022 में DMD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था, और उनकी पिछली अवधि अक्टूबर 2025 में समाप्त हुई।
- About HDFC Bank: Established in August 1994, headquartered in Mumbai, MD & CEO is Sashidhar Jagdishan, and the bank's tagline is "We Understand Your World."
- HDFC बैंक के बारे में अगस्त :1994 में स्थापित, मुख्यालय मुंबई, MD & CEO सशिधर जगदीशन हैं, और बैंक का टैगलाइन है "We Understand Your World!"

Ques: Which bank won the WSBI–ESBG Sustainable Development Goals (SDG) Award 2025 in the Climate Finance category?

कौन सा बैंक WSBI–ESBG सतत विकास लक्ष्य (SDG) पुरस्कार 2025 में क्लाइमेट फाइनेंस श्रेणी में जीत हासिल की?

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The State Bank of India (SBI) won the first edition of the WSBI–ESBG Sustainable Development Goals (SDG) Award 2025 in the Climate Finance category.
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने WSBI–ESBG सतत विकास लक्ष्य (SDG) पुरस्कार 2025 के पहले संस्करण में क्लाइमेट फाइनेंस श्रेणी में जीत हासिल की।
- The award was presented by the World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) and the European Savings and Retail Banking Group (ESBG) at the event held in Washington, USA.

• यह पुरस्कार वर्ल्ड सेविंग्स एंड रिटेल बैंकिंग इंस्टिट्यूट (WSBI) और यूरोपीयन सेविंग्स एंड रिटेल बैंकिंग ग्रुप (ESBG) द्वारा वाशिंगटन, अमेरिका में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया।

Ques: Which insurance company has been fined ₹1 crore by IRDAI for violating regulatory norms?

नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए IRDAI ने किस बीमा कंपनी पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है?

- A) HDFC ERGO General Insurance — एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस
- B) ICICI Lombard General Insurance — आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस
- C) Liberty General Insurance — लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस
- D) Tata AIG General Insurance — टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस
- E) Bajaj Allianz General Insurance — बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) imposed a ₹1 crore penalty on Liberty General Insurance for violations related to outsourcing, commission payments, and remuneration to intermediaries.
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर आउटसोर्सिंग, कमीशन भुगतान और मध्यस्थों को पारिश्रमिक देने से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया।
- The order was issued after an internal review identified multiple procedural lapses by the insurer.
- आंतरिक समीक्षा में कंपनी द्वारा कई प्रक्रियागत चूकें पाए जाने के बाद यह आदेश जारी किया गया।
- IRDAI also cautioned the insurer to strictly comply with guidelines to ensure policyholders' protection and transparency.
- IRDAI ने कंपनी को पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी।-
- This action is part of IRDAI's broader efforts to strengthen compliance and safeguard consumer interests in the insurance sector.

- यह कदम बीमा क्षेत्र में अनुपालन मजबूत करने और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के IRDAI के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

Ques: What is the SMART-CROP project and its objective?

SMART-CROP परियोजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?

- A) Crop insurance for farmers / किसानों के लिए फसल बीमा
- B) Sustainable Monitoring and Real-time Tracking for Crop Resilience and Optimal Practices supporting smallholder farmers / छोटे किसानों के लिए फसल लचीलापन और बेहतर प्रथाओं के लिए सतत निगरानी और वास्तविक समय ट्रैकिंग
- C) Organic farming promotion / जैविक खेती को बढ़ावा देना
- D) Irrigation infrastructure development / सिंचाई अवसंरचना विकास
- E) Market linkage for crops / फसलों के लिए बाज़ार संबंध

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The SMART-CROP project (Sustainable Monitoring and Real-time Tracking for Crop Resilience and Optimal Practices) is a three-year initiative aimed at supporting over 8,000 smallholder farmers across Karnataka and Telangana.
- SMART-CROP परियोजना सतत निगरानी और वास्तविक समय ट्रैकिंग फॉर क्रॉप) वर्षीय पहल है एक तीन (रेजिलिएंस एंड ऑप्टिमल प्रैक्टिसेज, जिसका उद्देश्य कर्नाटक और तेलंगाना में 8,000 से अधिक छोटे किसानों का समर्थन करना है।
- The project uses satellite imaging, remote sensing, and AI/ML analytics to provide real-time monitoring of crop stress.
- यह परियोजना उपग्रह इमेजिंग, रिमोट सेंसिंग और AI/ML एनालिटिक्स का उपयोग करके फसल तनाव की वास्तविक समय निगरानी प्रदान करती है।
- Partners in this initiative include SBI Foundation, University of Agricultural Sciences (UAS), International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), and Agribridge.
- इस पहल में SBI Foundation, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (UAS), International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), और Agribridge साझेदार हैं।

Ques: LIC recently increased its stake in which two FMCG companies?

एलआईसी ने हाल ही में किन दो एफएमसीजी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है?

- A) HUL and Britannia / एचयूएल और ब्रिटानिया
- B) Nestlé and ITC / नेस्ले और आईटीसी
- C) Tata Consumer Products and Dabur India / टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और डाबर इंडिया
- D) Marico and Godrej Consumer / मैरिको और गोदरेज कंज्यूमर
- E) Patanjali and Emami / पतंजलि और इमामी

Answer :Option C

Explanation / व्याख्या:

- Life Insurance Corporation (LIC) increased its stake in Tata Consumer Products by 2.012%, raising total shareholding to 8.645% from 6.633%.
- भारतीय जीवन बीमा निगम) LIC) ने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में अपनी हिस्सेदारी 2.012% बढ़ाकर 6.633% से 8.645% कर दी।
- In Dabur India, LIC added 2.067% equity, representing over 3.66 crore shares, increasing its holding to 6.985% from 4.918%.
- डाबर इंडिया में एलआईसी ने 2.067% हिस्सेदारी बढ़ाई, जो 3.66 करोड़ शेयरों से अधिक है, और हिस्सेदारी 4.918% से बढ़ाकर 6.985% कर दी।
- This reflects LIC's continued interest in India's fast-moving consumer goods (FMCG) sector.
- यह कदम एलआईसी की भारत के तेजी से बढ़ते उपभोक्ता वस्तु) FMCG) क्षेत्र में निरंतर रुचि को दर्शाता है।

Ques: Which authority organised the “Niveshak Shivir” in Amritsar on 1st November 2025, and what was its objective?

1 नवंबर 2025 को अमृतसर में “निवेशक शिविर” का आयोजन किस प्राधिकरण ने किया और इसका उद्देश्य क्या था?

- A) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) Securities and Exchange Board of India / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
- C) Investor Education and Protection Fund Authority / निवेशक शिक्षा और संरक्षण

निधि प्राधिकरण

D) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय

E) National Stock Exchange / राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), under the Ministry of Corporate Affairs, in collaboration with the Securities and Exchange Board of India (SEBI), successfully organised the “Niveshak Shivir” in Amritsar on 1st November 2025.
 - कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) के सहयोग से 1 नवंबर 2025 को अमृतसर में “निवेशक शिविर” का सफल आयोजन किया।
 - The initiative aimed to resolve issues related to unclaimed dividends, shares, and other investor services, providing a platform for grievance redressal.
 - इस पहल का उद्देश्य अप्राप्य लाभांश, शेयरों और अन्य निवेशक सेवाओं से संबंधित मुद्दों को हल करना था, और शिकायत निवारण के लिए एक मंच प्रदान करना था।
 - Following successful editions in Pune and Hyderabad, Amritsar became the next city to host this initiative, reaffirming IEPFA’s vision of building an investor-centric financial ecosystem across India. A total of 223 complaints were addressed during the event.
 - पुणे और हैदराबाद में सफल आयोजनों के बाद अमृतसर इस पहल की अगली मेजबानी करने वाली शहर बनी, जिससे भारत में निवेशककेंद्रित व-ितीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के IEPFA के दृष्टिकोण को पुनः पुष्टि मिली। इस आयोजन के दौरान कुल 223 शिकायतों का निवारण किया गया।
-

Ques: Which international institution has provided a USD 50 million loan to City Union Bank (CUB) to support MSMEs in adopting energy-efficient solutions?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को ऊर्जाकुशल समाधान अपनाने में सहायता के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने सिटी यूनियन बैंक (CUB) को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है?

- A) Asian Development Bank / एशियाई विकास बैंक
- B) International Monetary Fund / अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- C) World Bank / विश्व बैंक
- D) International Finance Corporation / अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम
- E) New Development Bank / न्यू डेवलपमेंट बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The International Finance Corporation (IFC), a member of the World Bank Group, has extended a USD 50 million loan to City Union Bank (CUB) for a period of 3 years.
- विश्व बैंक समूह की सदस्य संस्था अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने सिटी यूनियन बैंक (CUB) को 3 वर्षों के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है।
- The objective is to help MSMEs adopt energy-efficient and cost-effective technologies, thereby supporting India's net-zero target for 2070.
- इसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को ऊर्जा-प्र-कुशल और लागत-भावी तकनीकें अपनाने में सहायता करना है, जिससे भारत के 2070 नेटजीरो लक्ष्य में योगदान मिलेगा।-

About City Union Bank :

- Established : 1904
 - HQ : Kumbakonam, Tamil Nadu
 - MD & CEO : Dr. N. Kamakodi
 - Tagline : Trust and Excellence since 1904
-

Ques: In which month did UPI record its highest-ever transaction volume and value since its launch in 2016?

किस महीने में UPI ने 2016 में लॉन्च होने के बाद से अब तक की सबसे अधिक लेनदेन संख्या और मूल्य दर्ज किए?

- A) August 2025 / अगस्त 2025
- B) May 2025
- C) October 2025

D) September 2025

E) July 2025

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- In October 2025, UPI recorded 20.7 billion transactions worth ₹27.28 trillion, achieving its highest-ever performance since launch in April 2016.
 - अक्टूबर 2025 में UPI ने 20.7 बिलियन लेनदेन और ₹27.28 ट्रिलियन मूल्य के साथ लॉन्च के बाद से अब तक का सर्वोच्च स्तर दर्ज किया।
 - Compared to September 2025, transaction volume grew by 5% and value by 10%, reflecting strong growth in digital payments.
 - सितंबर 2025 की तुलना में लेनदेन संख्या में 5% और मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, जो डिजिटल भुगतान में मजबूत वृद्धि को दर्शाती है।
 - On average, 668 million daily transactions worth ₹87,993 crore per day were processed in October 2025.
 - अक्टूबर 2025 में औसतन प्रतिदिन 668 मिलियन लेनदेन हुए, जिनका मूल्य ₹87,993 करोड़ प्रति दिन रहा।
-

Ques: Which two organizations signed an MoU to provide doorstep Digital Life Certificate services to pensioners under the Employees' Pension Scheme, 1995?

कौनसी दो संस्थाओं ने कर्मचारियों के पेंशन योजना-, 1995 के तहत पेंशनरों को घर पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा प्रदान करने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए?

- A) India Post Payments Bank (IPPB) and Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) / इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक)IPPB) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)EPFO)
- B) State Bank of India and Life Insurance Corporation of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
- C) HDFC Bank and Pension Fund Regulatory Authority / एचडीएफसी बैंक और पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी
- D) ICICI Bank and Employees' Provident Fund Organisation / आईसीआईसीआई बैंक और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

E) Punjab National Bank and Ministry of Finance / पंजाब नेशनल बैंक और वित्त मंत्रालय

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- India Post Payments Bank (IPPB) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) to provide doorstep Digital Life Certificate (DLC) services to pensioners under the Employees' Pension Scheme, 1995.
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने कर्मचारियों के पेंशन योजना, 1995 के तहत पेंशनरों को घर पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) सेवा प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- The agreement was signed during EPFO's 73rd Foundation Day (1st November) between R. Viswesvaran, MD & CEO of IPPB, and Ramesh Krishnamurthi, Central Provident Fund Commissioner, EPFO.
- यह समझौता EPFO के 73वें स्थापना दिवस (1 नवंबर के अवसर पर (IPPB के एमडी और सीईओ आर विश्वेश्वरन और EPFO के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति के बीच किया गया।

About India Post Payments Bank Limited (IPPB) :

- Established : 2017
 - HQ : New Delhi, Delhi
 - CEO & MD : R. Viswesvaran
 - Tagline : Your Bank at Your Doorstep
-

Ques: As of October 31, 2025, what is the value of Rs 2,000 banknotes still in circulation in India, and what percentage has been returned since their withdrawal was announced?

31 अक्टूबर 2025 तक भारत में कितनी मूल्य की ₹2,000 के नोट अभी भी प्रचलन में हैं, और उनके वापसी की घोषणा के बाद कितने प्रतिशत नोट वापस किए गए हैं?

- A) Rs 10,000 crore / 75% returned / ₹10,000 करोड़ / 75% लौटाए गए
- B) Rs 3.56 lakh crore / 50% returned / ₹3.56 लाख करोड़ / 50% लौटाए गए

- C) Rs 1,000 crore / 90% returned / ₹1,000 करोड़ / 90% लौटाए गए
D) Rs 5,817 crore / 98.37% returned / ₹5,817 करोड़ / 98.37% लौटाए गए
E) Rs 50,000 crore / 80% returned / ₹50,000 करोड़ / 80% लौटाए गए

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) announced the withdrawal of Rs 2,000 banknotes from circulation on May 19, 2023.
 - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 19 मई, 2023 को ₹2,000 के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी।
 - The total value of Rs 2,000 banknotes in circulation, which was Rs 3.56 lakh crore on May 19, 2023, has declined to Rs 5,817 crore as of October 31, 2025.
 - 19 मई, 2023 को प्रचलन में ₹2,000 के नोटों का कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ था, जो 31 अक्टूबर, 2025 तक ₹5,817 करोड़ तक घट गया है।
 - Thus, 98.37% of the Rs 2,000 banknotes in circulation as on May 19, 2023, has since been returned.
 - इस प्रकार, 19 मई, 2023 को प्रचलन में मौजूद ₹2,000 के नोटों का 98.37% वापस किया जा चुका है।
 - Exchange of Rs 2,000 notes is available at the 19 issue offices of the RBI since May 19, 2023.
 - ₹2,000 के नोटों का आदान प्रदान-19 मई, 2023 से RBI के 19 जारी कार्यालयों पर उपलब्ध है।
-

Ques: Which bank executed its first gold trade as a Special Category Client (SCC) on the India International Bullion Exchange?

किस बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट (SCC) के रूप में अपना पहला गोल्ड ट्रेड किया?

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
C) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
D) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
E) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) executed its first gold trade on the India International Bullion Exchange (IIBX) as a Special Category Client (SCC), marking a key step in digitizing bullion transactions in India.
 - भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) पर स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के रूप में अपना पहला स्वर्ण व्यापार किया, जो भारत में बुलियन लेनदेन के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
 - This move enhances transparency, efficiency, and ease of access in the bullion import ecosystem, especially benefiting MSME jewellers.
 - यह कदम बुलियन आयात प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और पहुँच को बढ़ाता है, विशेष रूप से MSME ज्वेलर्स के लिए लाभकारी है।
 - SBI also became the first Trading-cum-Clearing (TCM) Member at IIBX in 2024.
 - SBI 2024 में IIBX का पहला ट्रेडिंग-क्लीयरिंग-कम-TCM) सदस्य भी बना था।
-

Ques: Which bank launched the annual employee excellence award titled 'SBI STAR'?

किस बैंक ने 'SBI STAR' नामक वार्षिक कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किया है?

- A) State Bank of India (SBI) / भारतीय स्टेट बैंक
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- D) Punjab National Bank (PNB) / पंजाब नेशनल बैंक
- E) Axis Bank / एक्सिस बैंक

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) has launched an annual employee excellence award titled 'SBI STAR' (Staff Talent Acknowledgement & Recognition) to honour employees' achievements beyond professional performance.
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 'SBI STAR' (स्टाफ टैलेंट एक्नॉलजमेंट & रिकग्निशन) नामक वार्षिक कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किया है, जो कर्मचारियों की पेशेवर प्रदर्शन से परे उपलब्धियों को सम्मानित करता है।
- The initiative recognises excellence in Arts, Literature, Sports, Culture, Social Work, and Environmental initiatives, promoting holistic engagement and employee well-being.
- यह पहल कला, साहित्य, खेल, संस्कृति, सामाजिक कार्य और पर्यावरणीय पहलों में उत्कृष्टता को पहचानती है, जिससे समग्र भागीदारी और कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा मिलता है।

Ques: Which company partnered with Razorpay Curlec to enable UPI transactions in Malaysia?

किस कंपनी ने मलेशिया में UPI लेनदेन सक्षम करने के लिए Razorpay Curlec के साथ साझेदारी की है?

- A) National Payments Corporation of India (NPCI) / राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत
- B) Paytm / पेटीएम
- C) Google Pay / गूगल पे
- D) PhonePe / फोनपे
- E) SBI Pay / एसबीआई पे

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- NPCI International Payments Limited (NPII) partnered with Razorpay Curlec, a wholly owned subsidiary of Razorpay, to enable Unified Payments Interface (UPI) transactions in Malaysia.
- NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NPII) ने मलेशिया में UPI लेनदेन सक्षम करने के लिए Razorpay की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Razorpay Curlec के साथ

साझेदारी की।

- This partnership allows Indian tourists and travelers in Malaysia to make real-time UPI payments at local merchants using their existing UPI apps, removing the need for foreign currency or international cards.
- इस साझेदारी के तहत, मलेशिया में भारतीय पर्यटक और यात्री अपने मौजूदा UPI ऐप्स का उपयोग करके स्थानीय व्यापारियों पर रीयल टाइम-UPI भुगतान कर सकेंगे, जिससे विदेशी मुद्रा या अंतरराष्ट्रीय कार्ड ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

Ques: The Government of India is planning to re-position which institution, established in 2021, as a global financial institution with a proposed new name Infrastructure Development Bank (IDB)?

भारत सरकार 2021 में स्थापित किस संस्था को एक वैश्विक वित्तीय संस्था के रूप में पुनर्स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसका नया प्रस्तावित नाम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक (IDB) होगा?

- A) SIDBI / सिडबी
- B) EXIM Bank / एक्सिम बैंक
- C) NaBFID / नैबफिड
- D) NABARD / नाबार्ड
- E) IFCI / आईएफसीआई

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Government of India plans to re-position the National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID), established in 2021, as a global financial institution.
- भारत सरकार 2021 में स्थापित नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) को एक वैश्विक वित्तीय संस्था के रूप में पुनर्स्थापित करने की योजना बना रही है।
- As part of this transformation, the bank's name is expected to be changed to Infrastructure Development Bank (IDB), indicating a shift in scale and scope.
- इस परिवर्तन के तहत बैंक का नाम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक (IDB) रखने की संभावना है, जो इसके कार्यक्षेत्र और स्तर में बदलाव का संकेत देता है।

- NaBFID is 100% government-owned and is classified as an All-India Financial Institution (AIFI) under the Reserve Bank of India Act, 1934.
- नैबफिड पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में है और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (AIFI) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

About NaBFID :

- Established : 2021
- HQ : Mumbai
- Chairman : K. V. Kamath

Ques: Which fintech company, in collaboration with Federal Bank, has introduced the Family Add-on Credit Card feature and launched India's first travel-focused shopping platform, Scapia Store?

किस फिनटेक कंपनी ने फेडरल बैंक के सहयोग से फैमिली ऐड-ऑन क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू की है और भारत का पहला यात्रा-केंद्रित शॉपिंग प्लेटफॉर्म Scapia Store लॉन्च किया है?

- A) Slice / स्लाइस
- B) Scapia / स्कापिया
- C) OneCard / वनकार्ड
- D) Fi Money / फाई मनी
- E) Cred / क्रेड

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Scapia, in collaboration with Federal Bank Limited, introduced the Family Add-on Credit Card feature and launched the Scapia Store, India's first travel-focused shopping platform.
- स्कापिया ने फेडरल बैंक लिमिटेड के सहयोग से फैमिली ऐड-ऑन क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू की और Scapia Store लॉन्च किया, जो भारत का पहला यात्रा-केंद्रित शॉपिंग प्लेटफॉर्म है।
- The initiative aims to strengthen Scapia's integrated ecosystem for travel enthusiasts in India.

- इस पहल का उद्देश्य भारत में यात्रा प्रेमियों के लिए स्कापिया के एकीकृत इकोसिस्टम को और मजबूत बनाना है।
- Primary cardholders can issue up to three add-on cards for family members aged 18 and above, with the option to set individual spending limits.
- मुख्य कार्डधारक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परिवार के सदस्यों के लिए तीन तक ऐड-ऑन कार्ड जारी कर सकते हैं और प्रत्येक कार्ड के लिए अलग-अलग खर्च सीमा तय कर सकते हैं।

About Federal Bank :

- Established : 1931
- HQ : Kochi, Kerala
- MD & CEO : KVS Manian
- Tagline : Your Perfect Banking Partner

Ques: Mahindra & Mahindra (M&M) is likely to sell its entire 3.45% stake in which bank for ₹682 crore through a block deal?

महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ₹682 करोड़ की ब्लॉक डील के माध्यम से अपनी पूरी 3.45% हिस्सेदारी किस बैंक में बेचने की तैयारी में है?

- A) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) RBL Bank / आरबीएल बैंक
- D) Yes Bank / यस बैंक
- E) IDFC First Bank / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Mahindra & Mahindra (M&M) is set to offload its entire 3.45% stake in RBL Bank through a block deal valued at ₹682 crore.
- महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) आरबीएल बैंक में अपनी पूरी 3.45% हिस्सेदारी ₹682 करोड़ की ब्लॉक डील के माध्यम से बेचने जा रही है।

- The floor price for the transaction is fixed at ₹317 per share, which is slightly below the market price.
- डील का फ्लोर प्राइस ₹317 प्रति शेयर तय किया गया है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से थोड़ा कम है।
- Kotak Securities is acting as the broker for this deal.
- इस डील के लिए कोटक सिक्योरिटीज को ब्रोकर नियुक्त किया गया है।
- Emirates NBD, which is already in the process of acquiring a 60% stake in RBL Bank through a primary infusion of ₹26,850 crore, is expected to be the major buyer.
- एमिरेट्स एनबीडी, जो ₹26,850 करोड़ के प्राथमिक निवेश के जरिए आरबीएल बैंक में 60% हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया में है, इस डील का मुख्य खरीदार होने की संभावना है।
- M&M had earlier, in 2023, bought a 3.53% stake in RBL Bank for ₹417 crore, giving a 64% return upon exit.
- M&M ने 2023 में 3.53% हिस्सेदारी ₹417 करोड़ में खरीदी थी, जिससे बाहर निकलते समय 64% रिटर्न मिला।
- Emirates NBD will also launch an open offer on December 12, 2025, at ₹280 per share, open till December 26.
- एमिरेट्स एनबीडी 12 दिसंबर 2025 को ₹280 प्रति शेयर पर ओपन ऑफर लाएगा, जो 26 दिसंबर तक खुला रहेगा।
- As per RBI norms, foreign investors can buy up to 74% stake in Indian private banks, but promoters' voting rights are capped at 26%.
- आरबीआई के नियमों के अनुसार, विदेशी निवेशक भारतीय निजी बैंकों में 74% तक हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, लेकिन प्रवर्तकों के वोटिंग अधिकार 26% तक सीमित हैं।
- In Q2FY26, RBL Bank's net profit stood at ₹179 crore, showing a 20% year-on-year decline due to lower net interest income.
- Q2FY26 में आरबीएल बैंक का शुद्ध लाभ ₹179 करोड़ रहा, जो 20% वार्षिक गिरावट को दर्शाता है, जिसका कारण कम शुद्ध ब्याज आय है।

Ques: Which bank has paused its plan to divest a majority stake in its subsidiary Nainital Bank Limited (NBL) and decided to focus on strengthening it instead?

किस बैंक ने अपनी सहायक कंपनी नैनीताल बैंक लिमिटेड (NBL) में बहुसंख्यक हिस्सेदारी बेचने की योजना को रोक दिया है और बैंक को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है?

A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक

- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
C) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
D) Canara Bank / केनरा बैंक
E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Bank of Baroda (BoB) has decided to pause its plan to divest a majority shareholding in its subsidiary Nainital Bank Limited (NBL) and will instead focus on strengthening the bank's operations.
 - बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने अपनी सहायक कंपनी नैनीताल बैंक लिमिटेड (NBL) में बहुसंख्यक हिस्सेदारी बेचने की योजना रोक दी है और अब बैंक के सुदृढीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
 - In Q2 FY26, BoB infused ₹169 crore into NBL, raising its subscribed capital to ₹165.72 crore and share premium to ₹258.12 crore, thereby boosting NBL's capital base.
 - वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में, BoB ने NBL में ₹169 करोड़ का निवेश किया, जिससे उसका सब्सक्राइब्ड कैपिटल ₹165.72 करोड़ और शेयर प्रीमियम ₹258.12 करोड़ तक बढ़ गया, जिससे बैंक की पूंजी आधार को मजबूती मिली।
 - Currently, Bank of Baroda holds a 98.57% stake in Nainital Bank Limited.
 - वर्तमान में, बैंक ऑफ बड़ौदा की नैनीताल बैंक लिमिटेड में 98.57% हिस्सेदारी है।
-

Genius
EXAM
**Ques: What was the net profit of the State Bank of India (SBI) in Q2 FY26?
Q2 FY26 में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का शुद्ध लाभ कितना रहा?**

- A) ₹17,800 crore / ₹17,800 करोड़
B) ₹19,200 crore / ₹19,200 करोड़
C) ₹20,160 crore / ₹20,160 करोड़
D) ₹22,500 crore / ₹22,500 करोड़
E) ₹25,000 crore / ₹25,000 करोड़

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) reported a net profit of ₹20,160 crore in Q2 FY26, marking a 10% year-on-year (YoY) growth.
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने Q2 FY26 में ₹20,160 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो 10% वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।
- The rise in profit was driven by the sale of a 13.18% stake in Yes Bank, which generated a profit of ₹4,593 crore.
- लाभ में बढ़ोतरी का मुख्य कारण यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी की बिक्री रही, जिससे ₹4,593 करोड़ का लाभ हुआ।
- Net Interest Income (NII) grew 3.28% YoY, while the Net Interest Margin (NIM) for Q2 FY26 stood at 3.09%, slightly lower than 3.27% last year.
- नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में 3.28% वार्षिक वृद्धि हुई, जबकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 3.09% रहा, जो पिछले वर्ष के 3.27% से थोड़ा कम है।
- Advances grew 12.73% YoY, and Deposits rose 9.27% YoY, reflecting robust business growth.
- ऋण (Advances) में 12.73% वृद्धि और जमाओं (Deposits) में 9.27% वृद्धि दर्ज की गई।
- Asset quality improved: Gross NPA: 1.73% (improved by 40 bps YoY) Net NPA: 0.42% (improved by 11 bps YoY)
- संपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ: ग्रॉस NPA: 1.73% (40 बेसिस पॉइंट का सुधार) नेट NPA: 0.42% (11 बेसिस पॉइंट का सुधार)

Ques: Which bank has launched an EPF remittance service in collaboration with EPFO?

किस बैंक ने EPFO के साथ मिलकर EPF रेमिटेंस सेवा शुरू की है?

- A) Karur Vysya Bank / करूर व्यस्या बैंक
- B) City Union Bank / सिटी यूनियन बैंक
- C) South Indian Bank / साउथ इंडियन बैंक
- D) Federal Bank / फेडरल बैंक
- E) None of the Above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- City Union Bank (CUB) has partnered with the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) to launch an EPF remittance service.
- सिटी यूनियन बैंक (CUB) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ मिलकर EPF रेमिटेंस सेवा शुरू की है।
- The service enables corporate customers of the bank to remit provident fund contributions directly through CUB's net banking portal.
- यह सेवा बैंक के कॉर्पोरेट ग्राहकों को नेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से PF राशि जमा करने की अनुमति देती है।
- The launch event was held in Chennai, Tamil Nadu, in the presence of Vijay Anandh (Executive Director, CUB) and Maneesh Agnihotri (Regional PF Commissioner, Tamil Nadu).
- लॉन्च कार्यक्रम चेन्नई, तमिलनाडु में विजय आनंद कारी निदेशककार्य), CUB) और मनीष अग्निहोत्री क्षेत्रीय)PF आयुक्त, तमिलनाडुकी उपस्थिति में आयोजित किया गया। (

Ques: SBI and France's Amundi will jointly divest how much stake in SBI Funds Management via IPO?

एसबीआई और फ्रांस की एमुंडी आईपीओ के माध्यम से एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट में कितनी हिस्सेदारी बेचेंगे?

- A) 5%
- B) 7%
- C) 8%
- D) 10%
- E) 12%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) and France's Amundi have jointly decided to divest a total of 10% stake in SBI Funds Management Ltd (SBIFML) through an Initial Public Offering (IPO).
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और फ्रांस की एमुंडी ने एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड (SBIFML) में कुल 10% हिस्सेदारी आईपीओ के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया है।

- Out of this, SBI will sell 6.3% and Amundi will sell 3.7%, maintaining their proportionate divestment.
- इसमें से एसबीआई अपनी 6.3% हिस्सेदारी और एमुंडी अपनी 3.7% हिस्सेदारी बेचेंगे, जिससे कुल 10% हिस्सेदारी का लेनदेन होगा।
- Currently, SBIFML is India's largest mutual fund with a market share of 15.55% and AUM of ₹16.32 lakh crore (as of Sept 2025).
- वर्तमान में, SBIFML भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 15.55% और AUM सितंबर 2025 तक ₹16.32 लाख करोड़ है।

Ques: Which companies have introduced a dual loan financing program to make electric vehicles more affordable in India?

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक किफायती बनाने के लिए कौन सी कंपनियों ने डुअल लोन फाइनेंसिंग प्रोग्राम शुरू किया है?

- A) Tata Motors and HDFC Bank / टाटा मोटर्स और HDFC बैंक
- B) JSW MG Motor India and Axis Bank / JSW MG मोटर इंडिया और एक्सिस बैंक
- C) Mahindra Electric and ICICI Bank / महिंद्रा इलेक्ट्रिक और ICICI बैंक
- D) Hyundai Motor India and SBI / हुंडई मोटर इंडिया और SBI
- E) Maruti Suzuki and Punjab National Bank / मारुति सुजुकी और पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- JSW MG Motor India and Axis Bank launched a dual loan financing program to make electric vehicles more affordable for Indian consumers.
- JSW MG मोटर इंडिया और एक्सिस बैंक ने भारतीय ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक किफायती बनाने हेतु डुअल लोन फाइनेंसिंग प्रोग्राम शुरू किया।
- The program allows separate loans for the EV and its battery under MG's Battery-as-a-Service (BaaS) model, with up to 100% on-road financing and battery loan tenures of up to eight years.
- इस प्रोग्राम के तहत ग्राहक MG के बैटरी-एज़-ए-सर्विस) BaaS) मॉडल के अंतर्गत वाहन और बैटरी के लिए अलग-अलग ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 100% ऑन-रोड फाइनेंसिंग और आठ वर्षों तक बैटरी ऋण अवधि शामिल है।

- The BaaS model was first launched in September 2024 to reduce high upfront costs associated with EV purchases.
- BaaS मॉडल को पहली बार सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था ताकि इलेक्ट्रिक वाहन खरीद से जुड़े उच्च प्रारंभिक लागत को कम किया जा सके।

Ques: What is the name of Paytm's new AI-powered travel app?

Paytm के नए AI-सक्षम ट्रैवल ऐप का नाम क्या है?

- A) Paytm Travel+ / पेटीएम ट्रैवल+
- B) Paytm Check-in / पेटीएम चेकइन-
- C) Paytm Journey / पेटीएम जर्नी
- D) Paytm Trip Planner / पेटीएम ट्रिप प्लानर
- E) None of the Above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Paytm has launched a new AI-powered travel app named 'Paytm Check-in', allowing users to manage bookings across flights, trains, buses, and metro in one platform.
- Paytm ने 'Paytm Check-in' नामक नया AI-सक्षम ट्रैवल ऐप लॉन्च किया है, जो उपयोगकर्ताओं को फ्लाइट, ट्रेन, बस और मेट्रो की बुकिंग एक ही प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थित करने की सुविधा देता है।
- The app features an AI assistant that helps users browse and book travel through a conversational interface, recommends destinations, and creates personalized itineraries.
- इस ऐप में एक AI असिस्टेंट शामिल है जो उपयोगकर्ताओं को संवादी इंटरफेस के माध्यम से यात्रा ब्राउज़ और बुक करने में मदद करता है, गंतव्य सुझाता है और व्यक्तिगत यात्रा योजनाएँ तैयार करता है।
- Currently, the app is in its early beta stage, with features being tested and refined for better user experience.
- वर्तमान में यह ऐप प्रारंभिक बीटा चरण में है, जिसमें विशेषताओं का परीक्षण और सुधार जारी है।

Ques: Which two regulators are collaborating to introduce bond derivatives in India?

भारत में बॉन्ड डेरिवेटिव्स शुरू करने के लिए कौन से दो नियामक संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं?

- A) RBI and IRDAI / आरबीआई और IRDAI
- B) SEBI and RBI / सेबी और आरबीआई
- C) NABARD and SEBI / NABARD और सेबी
- D) SIDBI and RBI / SIDBI और आरबीआई
- E) PFRDA and SEBI / PFRDA और सेबी

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) and the Reserve Bank of India (RBI) are jointly working to introduce bond derivatives in India to expand and deepen the country's bond market.
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मिलकर भारत में बॉन्ड डेरिवेटिव्स शुरू करने पर काम कर रहे हैं ताकि देश के बॉन्ड बाजार को गहराई और विस्तार दिया जा सके।
- The initiative will also allow banks to trade in commodity derivatives and potentially enable Foreign Portfolio Investors (FPIs) to participate in non-cash settled, non-agricultural commodity derivative contracts.
- इस पहल के तहत बैंकों को क्मोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने और एफपीआई को गैर-नकद निपटान वाले, गैर-कृषि क्मोडिटी डेरिवेटिव्स में व्यापार करने की अनुमति दी जा सकती है।
- SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey noted that this move will make debt instruments more attractive for retail investors, while India's corporate bond market remains smaller compared to the loan market.
- सेबी के अध्यक्ष तूहिन कांता पांडे ने कहा कि यह कदम खुदरा निवेशकों के लिए ऋण साधनों को और आकर्षक बनाएगा, जबकि भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार ऋण बाजार की तुलना में अभी भी छोटा है।

Ques: What was the cumulative profit of Public Sector Banks (PSBs) in Q2 FY26?

Q2 FY26 में पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) का कुल लाभ कितना रहा?

- A) ₹45,547 crore
- B) ₹49,456 crore
- C) ₹50,000 crore
- D) ₹93,674 crore
- E) ₹85,520 crore

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Public Sector Banks (PSBs), led by the State Bank of India (SBI), posted a record cumulative profit of ₹49,456 crore in Q2 FY26, marking a 9% year-on-year growth.
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के नेतृत्व वाले पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) ने Q2 FY26 में 49,456 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कुल लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि को दर्शाता है।
- SBI alone contributed 40% of the total PSB profit, with a net profit of ₹20,160 crore, up 10% from the previous year.
- केवल SBI ने कुल PSB लाभ का 40% योगदान दिया, जिसमें 20,160 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ, जो पिछले वर्ष से 10% अधिक है।
- Indian Overseas Bank (IOB) recorded the highest profit growth of 58%, and the aggregate PSB profit for H1 FY26 crossed ₹90,000 crore for the first time.
- इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने 58% की सबसे अधिक लाभ वृद्धि दर्ज की, और H1 FY26 में PSBs का समग्र लाभ पहली बार 90,000 करोड़ रुपये को पार कर गया।

Ques: What is the total balance in Jan Dhan accounts as of October 22, 2025?

22 अक्टूबर 2025 तक जन धन खातों में कुल शेष राशि कितनी है?

- A) ₹1.85 lakh crore
- B) ₹2.15 lakh crore
- C) ₹2.75 lakh crore
- D) ₹3.00 lakh crore

E) ₹2.50 lakh crore

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- As per government data, the total balance in Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts crossed ₹2.75 lakh crore as of October 22, 2025, with 56.85 crore accounts opened.
 - सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) खातों में कुल शेष राशि 22 अक्टूबर 2025 तक ₹2.75 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जिसमें 56.85 करोड़ खाते शामिल हैं।
 - Public sector banks hold the majority of deposits — ₹2.15 lakh crore, followed by regional rural banks with ₹51,489 crore, and private banks with ₹8,149 crore.
 - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास अधिकतम जमा राशि — ₹2.15 लाख करोड़, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास ₹51,489 करोड़, और निजी बैंकों के पास ₹8,149 करोड़ है।
 - The government and banks have been actively working to revive inactive accounts through Financial Inclusion programs and KYC re-verification drives.
 - सरकार और बैंकों ने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम और KYC पुनसत्यापन अभियान के माध्यम से निष्क्रिय खातों को पुनर्जीवित करने के लिए सक्रिय प्रयास किए हैं।
-

Ques: Which Indian company recently became the sixth to cross the \$100 billion market capitalisation mark?

कौन सी भारतीय कंपनी हाल ही में \$100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन का आंकड़ा पार करने वाली छठी कंपनी बनी है?

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B) Bharti Airtel / भारती एयरटेल
- C) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- D) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- E) Tata Consultancy Services / टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) became the sixth Indian company to cross the \$100 billion market-cap mark, with its market value reaching \$100 billion (₹8.86 trillion).
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) \$100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी बन गई, इसका मार्केट वैल्यू \$100 बिलियन (₹8.86 ट्रिलियन) तक पहुंच गया।
- SBI's share price gained over 1% to hit a record high, reflecting strong investor confidence.
- एसबीआई के शेयर में 1% से अधिक की वृद्धि हुई और यह रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा, जो निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है।
- The companies ahead of SBI in the \$100 billion club are Reliance Industries (\$228 bn), HDFC Bank (\$171 bn), Bharti Airtel (\$135 bn), TCS (\$123 bn), and ICICI Bank (\$106 bn).
- \$100 बिलियन क्लब में एसबीआई से आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज (\$228 अरब), एचडीएफसी बैंक (\$171 अरब), भारती एयरटेल (\$135 अरब), टीसीएस (\$123 अरब), और आईसीआईसीआई बैंक (\$106 अरब) हैं।
- SBI aims to enter the top 10 global banks by market capitalisation, according to SBI Chairman C.S. Setty.
- एसबीआई का लक्ष्य मार्केट कैप के आधार पर शीर्ष 10 वैश्विक बैंकों में शामिल होना है, जैसा कि एसबीआई के अध्यक्ष सीसेटी ने बताया .एस.।

Ques: Which bank declared Reliance Communications' loan account as "fraud"?

किस बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशंस का ऋण खाता के रूप में घोषित किया "धोखाधड़ी"?

- A) SBI / एसबीआई
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) IDBI Bank / आईडीबीआई बैंक
- D) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- E) Axis Bank / एक्सिस बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- IDBI Bank declared Reliance Communications' (RCom) loan account of about ₹750 crore as "fraud" due to alleged diversion or misuse of funds.
- आईडीबीआई बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के लगभग (आरकॉम) ₹750 करोड़ के ऋण खाते को कथित फंड के अपव्ययके रूप में घोषित किया। "धोखाधड़ी" दुरुपयोग के कारण/
- Reliance Communications has been under insolvency proceedings since June 2019 after defaulting on its debt obligations.
- रिलायंस कम्युनिकेशंस जून 2019 से अपने ऋण दायित्वों में चूक के बाद दिवालियापन प्रक्रिया के अधीन है।
- The Enforcement Directorate has provisionally attached assets worth Rs 3,084 crore linked to Anil Ambani in a money laundering investigation involving Reliance Home Finance and Reliance Commercial Finance.
- प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी से संबंधित 3,084 करोड़ रुपये के संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है।

Ques: Which company received in-principle approval from the Reserve Bank of India to issue Prepaid Payment Instruments?

किस कंपनी को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्रिन्सिपल स्वीकृति मिली?

- A) Paytm Payments Bank / पेटीएम पेमेंट्स बैंक
- B) Junio Payments Private Limited / जुनियो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
- C) PhonePe / फोनपे
- D) MobiKwik / मोबिक्विक
- E) Razorpay / रेज़रपे

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Junio Payments Private Limited (JPPL), a wholly-owned subsidiary of FirstPay Technologies Private Limited, received in-principle authorisation from the

Reserve Bank of India to issue Prepaid Payment Instruments.

- जूनियो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (JPPL), फर्स्टपे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्रिन्सिपल स्वीकृति मिली।
- The approval, granted under Section 18 read with Section 10(2) of the Payment and Settlement Systems Act, 2007, allows JPPL to launch a digital wallet linked to the Unified Payments Interface (UPI).
- यह स्वीकृति, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 18 को धारा 10(2) के साथ पढ़कर प्रदान की गई है, JPPL को UPI से लिंक डिजिटल वॉलेट लॉन्च करने की अनुमति देती है।

Ques: Which regulatory body has urged social media platforms and search engines to implement stronger safeguards against fraudulent investment activities?

कौन सा नियामक संगठन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन से धोखाधड़ी वाली निवेश गतिविधियों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करने का आग्रह कर रहा है?

- A) RBI / आरबीआई
- B) SEBI / सेबी
- C) IRDAI / आईआरडीएआई
- D) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- E) FSSAI / एफएसएसएआई

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has urged major social media platforms and internet search engines to implement stronger safeguards to prevent fraudulent investment activities.
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सर्च इंजनों से धोखाधड़ी वाली निवेश गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करने का आग्रह किया है।
- This initiative aligns with the International Organization of Securities Commissions (IOSCO)'s global call to protect investors from online financial

harm.

- यह पहल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोगों के संगठन (IOSCO) की वैश्विक पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य निवेशकों को ऑनलाइन वित्तीय जोखिम से सुरक्षित रखना है।
- SEBI has advised investors to verify the registration status of entities and use validated UPI handles and authentic trading applications for all transactions.
- SEBI ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे संस्थाओं की पंजीकरण स्थिति सत्यापित करें और सभी लेनदेन के लिए मान्य UPI हैंडल और प्रमाणित ट्रेडिंग ऐप का उपयोग करें।

Ques: What is the total corpus of the AgriSURE Fund launched by NABARD and the Union Agriculture Ministry?

NABARD और कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए AgriSURE फंड की कुल राशि कितनी है?

- A) ₹500 crore
- B) ₹600 crore
- C) ₹750 crore
- D) ₹800 crore
- E) ₹1000 crore

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- AgriSURE Fund (Agri Fund for Start-ups & Rural Enterprises) is a ₹750 crore fund jointly promoted by the Union Agriculture Ministry and NABARD to support agri start-ups and rural enterprises.
- AgriSURE Fund (Agri Fund for Start-ups & Rural Enterprises) ₹750 करोड़ का फंड है, जिसे कृषि मंत्रालय और NABARD द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है, ताकि कृषि स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों को प्रोत्साहन मिल सके।
- Of the total corpus, ₹250 crore each is contributed by the Government of India and NABARD, while the remaining ₹250 crore will be mobilised from private investors and institutions.
- कुल राशि में से ₹250 करोड़ भारत सरकार और ₹250 करोड़ NABARD द्वारा प्रदान किए गए हैं, जबकि शेष ₹250 करोड़ निजी निवेशकों और संस्थानों से जुटाए जाएंगे।
- The fund is registered with SEBI as a Category-II Alternative Investment Fund (AIF), and NABVENTURES Ltd., a wholly owned subsidiary of NABARD, will act as its Investment Manager.

• यह फंड SEBI के साथ Category-II Alternative Investment Fund (AIF) के रूप में पंजीकृत है, और NABVENTURES Ltd., जो NABARD की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसे Investment Manager के रूप में संचालित करेगी।

Ques: Which bank has partnered with NPST to deploy UPI 123Pay, a voice-based UPI payment system for users without internet access?

किस बैंक ने एनपीएसटी के साथ साझेदारी कर यूपीआई 123पे, इंटरनेट रहित उपयोगकर्ताओं के लिए वॉइसप्रणाली भुगतान यूपीआई आधारित-, लागू करने का निर्णय लिया है?

- A) Indian Bank / इंडियन बैंक
- B) Indian Overseas Bank / इंडियन ओवरसीज बैंक
- C) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- D) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Indian Overseas Bank (IOB) has selected Network People Services Technologies Limited (NPST) to deploy UPI 123Pay, a voice-based UPI payment system.
- इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (NPST) को यूपीआई 123पे, एक वॉइसप्रणाली भुगतान यूपीआई आधारित-, लागू करने के लिए चुना है।
- The system targets around 850 million Indians who do not use traditional UPI apps.
- यह प्रणाली लगभग 85 करोड़ भारतीयों को लक्षित करती है जो पारंपरिक यूपीआई ऐप्स का उपयोग नहीं करते।
- NPST will implement this solution in collaboration with MissCallPay.
- एनपीएसटी इसे मिसकॉलपे के साथ साझेदारी में लागू करेगी।
- Users can give a missed call, receive an IVR callback, and complete transactions through voice or keypad prompts without internet or mobile data.
- उपयोगकर्ता मिसड कॉल देकर, आईवीआर कॉलबैक प्राप्त कर, बिना इंटरनेट या मोबाइल डेटा के वॉइस या कीपैड इनपुट के माध्यम से भुगतान पूरा कर सकते हैं।
- The IVR platform supports 12 Indian languages and allows checking balances,

last five transactions, dispute raising, and UPI PIN management.

- यह आईवीआर प्लेटफॉर्म 12 भारतीय भाषाओं को समर्थन देता है और उपयोगकर्ताओं को बैलेंस जांचने, पिछली 5 लेनदेन देखने, विवाद दर्ज करने और यूपीआई पिन प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करता है।

About Indian Overseas Bank :

- Established : 1937
- HQ : Chennai
- MD & CEO : Shri Ajay Kumar Srivastava,
- Tagline : Good People to Grow With

Ques: Which bank launched 'M' Circle, a women-focused banking proposition offering discounts on locker rentals and preferential loan rates?

किस बैंक ने 'एम सर्कल' लॉन्च किया, जो महिलाओं के लिए बैंकिंग प्रस्ताव है और लॉकर किराया पर छूट और वरीय ऋण दरें प्रदान करता है?

- A) AU Small Finance Bank / एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- AU Small Finance Bank (AU SFB) launched 'M' Circle, a specialized banking proposition tailored for women.
- एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU SFB) ने 'एम सर्कल' लॉन्च किया, जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया बैंकिंग प्रस्ताव है।
- Customers under 'M' Circle enjoy 25% additional discount on locker rentals, preferential loan rates with 0.2% lower interest, and exclusive offers from brands like Nykaa, Ajio Luxe, Kalyan Jewellers, BookMyShow, Zepto, and Swiggy.

- 'एम सर्कल' के ग्राहक लॉकर किराया पर 25% अतिरिक्त छूट, 0.2% कम ब्याज दर पर वरीय ऋण दर, और Nykaa, Ajio Luxe, Kalyan Jewellers, BookMyShow, Zepto और Swiggy जैसी ब्रांडों पर विशेष ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं।

About AU Small Finance Bank:

- Established : 2017
- HQ : Jaipur, Rajasthan
- CEO & MD : Sanjay Agarwal
- Tagline : Badlaav Humse Hai

Ques: Which company received a USD 331 million loan from the Asian Development Bank (ADB) to support its hybrid renewable energy project in Andhra Pradesh?

किस कंपनी को एशियाई विकास बैंक (ADB) से आंध्र प्रदेश में अपने हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए 331 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ है?

- A) Adani Green Energy Ltd / अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
- B) ReNew Energy Global Plc / रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी
- C) Tata Power Renewable Energy Ltd / टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
- D) NTPC Green Energy Ltd / एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
- E) JSW Energy Ltd / जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) has provided USD 331 million in debt financing to ReNew Energy Global Plc.
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी को 331 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण वित्तपोषण प्रदान किया है।
- The funding will support its 837 megawatt-peak (MWp) hybrid renewable energy project in Andhra Pradesh, which integrates wind, solar, and battery storage.
- यह फंडिंग आंध्र प्रदेश में 837 मेगावाट) पीक-MWp) हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा

परियोजना का समर्थन करेगी, जो पवन, सौर और बैटरी भंडारण को एकीकृत करती है।

- The loan is part of a USD 477 million funding package, with the remaining USD 146 million to be raised through co-financing from other lenders.
- यह ऋण 477 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फंडिंग पैकेज का हिस्सा है, जिसमें शेष 146 मिलियन अमेरिकी डॉलर अन्य ऋणदाताओं से सहजाएंगे। जुटाए से माध्यम के वित्तपोषण-
- The project includes a 415 MWh Battery Energy Storage System (BESS).
- परियोजना में 415 मेगावाट (घंटा-MWh) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) शामिल है।

Ques: IN-SPACE and SIDBI have launched a ₹1,000 crore Venture Capital Fund for which sector?

IN-SPACE और SIDBI ने ₹1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड किस क्षेत्र के लिए शुरू किया है?

- A) Defence Sector / रक्षा क्षेत्र
- B) Agriculture Sector / कृषि क्षेत्र
- C) Space Sector / अंतरिक्ष क्षेत्र
- D) Manufacturing Sector / विनिर्माण क्षेत्र
- E) Renewable Energy Sector / अक्षय ऊर्जा क्षेत्र

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The ₹1,000 crore fund jointly launched by **IN-SPACE** and **SIDBI Venture Capital (SVCL)** aims to provide **early-stage and growth capital** to startups in the Indian **space sector**, covering launch technologies, satellites, payload systems, and communication platforms.
- **IN-SPACE और SIDBI वेंचर कैपिटल (SVCL)** द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया ₹1,000 करोड़ का फंड भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रारंभिक और विकास पूंजी प्रदान करेगा, जिसमें लॉन्च तकनीक, उपग्रह, पेलोड सिस्टम और संचार प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
- Approved by the Union Cabinet in October 2024, with SVCL as Fund Manager, the fund is expected to **boost India's private space ecosystem**, enabling startups to innovate, test indigenous technologies, and scale operations confidently.

• अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी और SVCL को फंड मैनेजर नियुक्त किए जाने के बाद, यह फंड भारत के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा, जिससे स्टार्टअप्स नवाचार करने, स्वदेशी तकनीकों का परीक्षण करने और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करने में सक्षम होंगे।

Ques: Which company won the 'Digital Insurer of the Year' award for the third time at the 29th Asia Insurance Industry Awards (AIIA) 2025?

29वें एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवार्ड्स (AIIA) 2025 में 'डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर' का तीसरी बार पुरस्कार किस कंपनी ने जीता?

- A) ICICI Lombard / आईसीआईसीआई लोम्बार्ड
B) Bajaj Allianz General Insurance / बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस
C) Tata AIG General Insurance / टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस
D) HDFC ERGO General Insurance / एचडीएफसी ईआरगो जनरल इंश्योरेंस
E) Go Digit General Insurance Limited / गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Go Digit General Insurance Limited (Digit Insurance) won the 'Digital Insurer of the Year' award for the third time at the 29th Asia Insurance Industry Awards (AIIA) 2025.
- गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड डिजिट इंश्योरेंस (ने 29वें एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवार्ड्स) AIIA) 2025 में 'डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर' का तीसरी बार पुरस्कार जीता।
- Jasleen Kohli, MD and CEO of Digit Insurance, also won the 'Woman Leader of the Award' at the same event.
- डिजिट इंश्योरेंस की एमडी और सीईओ जसलीन कोहली को भी इसी कार्यक्रम में 'वुमन लीडर ऑफ द अवार्ड' से सम्मानित किया गया।
- This recognition marks Digit Insurance's overall 7th win at the AIIA awards, including previous wins for "General Insurance Company of the Year" (2019, 2020, 2024) and "Digital Insurer of the Year" (2021, 2023, 2025).
- यह सम्मान डिजिट इंश्योरेंस के AIIA अवार्ड्स में कुल 7वें जीत को दर्शाता है, जिसमें पहले "जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर" (2019, 2020, 2024) और "डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर" (2021, 2023, 2025) पुरस्कार शामिल हैं।

Other winners in 29th Asia Insurance Industry Awards (AIIA) 2025:

- General Insurance Company of the Year : Alliance General Insurance Company (Malaysia) Berhad
- Health Insurance Company of the Year : Nan Shan Life Insurance Co., Limited
- Life Insurance Company of the Year : HSBC Life (International) Limited
- Technology Initiative of the Year : Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AIC) for SEWANxt platform

Ques: What measure has the Reserve Bank of India (RBI) proposed to boost long-term lending by NBFCs for high-quality infrastructure projects?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने उच्च लिए के प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाले गुणवत्ता-NBFCs द्वारा दी जाने वाली लंबी अवधि की ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उपाय प्रस्तावित किया है?

- A) Increasing interest rates on NBFC loans / NBFC ऋण पर ब्याज दर बढ़ाना
- B) Lowering risk weights on high-quality infrastructure projects / उच्च गुणवत्ता-करना कम भार जोखिम पर प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाले
- C) Mandating higher collateral for project loans / प्रोजेक्ट लोन के लिए उच्च सुरक्षा राशि अनिवार्य करना
- D) Limiting NBFC exposure to infrastructure sector / इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में NBFC की हिस्सेदारी सीमित करना
- E) Introducing tax incentives for NBFCs / NBFCs के लिए कर प्रोत्साहन लागू करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The RBI has proposed reducing risk weights on high-quality infrastructure projects financed by NBFCs to encourage long-term project lending.
- RBI ने NBFCs द्वारा वित्तपोषित उच्चगुण-वत्ता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर जोखिम भार कम करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि लंबी अवधि की परियोजना ऋण सुविधा को बढ़ावा दिया जा सके।

- Projects with at least 10% repayment of the sanctioned amount will attract a 50% risk weight, and those with 5–10% repayment will attract 75%, instead of the previous 100%.
- जिन परियोजनाओं ने स्वीकृत राशि का कम से कम 10% चुका दिया है, उन पर 50% जोखिम भार लगेगा, और 5–10% भुगतान करने वाली परियोजनाओं पर 75% जोखिम भार लगेगा, पहले की 100% के बजाय।
- If projects fail to meet repayment or quality criteria later, a 100% risk weight will apply.
- यदि परियोजनाएं बाद में पुनर्भुगतान या गुणवत्ता मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, तो 100% जोखिम भार लागू होगा।
- To qualify as high-quality, a project must have completed one year of satisfactory operations after the Date of Commencement of Commercial Operations (DCCO).
- उच्चलिफे के होने वाले गुणवत्ता-, परियोजना को वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि (DCCO) के बाद एक वर्ष तक संतोषजनक संचालन पूरा करना आवश्यक है।
- Feedback on the draft is open till 21st November 2025, with implementation effective from 1st April 2026.
- इस मसौदे पर सुझाव 21 नवंबर 2025 तक आमंत्रित हैं, और इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा।

Ques: UIDAI partnered with which organization to improve the reliability of India's digital identity system for minors?

नाबालिगों के लिए भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए UIDAI ने किस संगठन के साथ साझेदारी की?

- A) World Bank / विश्व बैंक
- B) Behavioural Insights Limited (BIL) / बिहेवियरल इंसाइट्स लिमिटेड
- C) NITI Aayog / नीति आयोग
- D) UNICEF / यूनिसेफ
- E) CSIR / सीएसआईआर

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- UIDAI has partnered with Behavioural Insights Limited (BIL), a global research consultancy, to enhance the adoption of the Mandatory Biometric Update (MBU) for children aged 5 to 15, ensuring their Aadhaar credentials remain current and fully functional.
- UIDAI ने नाबालिगों की डिजिटल पहचान प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए वैश्विक अनुसंधान कंसल्टेंसी Behavioural Insights Limited (BIL) के साथ साझेदारी की है, ताकि 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) को बढ़ावा दिया जा सके और उनके आधार प्रमाणपत्र वर्तमान और पूरी तरह से कार्यात्मक बने रहें।
- UIDAI has announced a one-year fee waiver for MBU services for children aged 7 to 15, effective from October 1, 2025.
- UIDAI ने 7 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए MBU सेवाओं पर एक वर्षीय शुल्क माफी की घोषणा की है, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है।

Ques: RBI recently recognised SRPA as the SRO for which sector?

हाल ही में RBI ने SRPA को किस सेक्टर के लिए SRO के रूप में मान्यता दी?

- A) Microfinance Sector / माइक्रोफाइनेंस सेक्टर
- B) NBFC Sector / एनबीएफसी सेक्टर
- C) Fintech Sector / फिनटेक सेक्टर
- D) Payment System Operators Sector / भुगतान प्रणाली ऑपरेटर सेक्टर
- E) Banking Sector / बैंकिंग सेक्टर

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has recognised the Self-Regulated PSO Association (SRPA) as the Self-Regulatory Organisation (SRO) for the Payment System Operators (PSO) sector.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने Self-Regulated PSO Association (SRPA) को Payment System Operators (PSO) सेक्टर के लिए Self-Regulatory Organisation (SRO) के रूप में मान्यता दी है।
- The recognition follows RBI's Framework for Recognition of SRO for PSOs (October 2020) and aligns with the Omnibus Framework for Recognition of

SROs for Regulated Entities (March 2024).

- यह मान्यता RBI के 2020 और 2024 में जारी संबंधित SRO फ्रेमवर्क के अनुसार दी गई है।
- With SRPA's recognition, the financial sector now has multiple officially recognised SROs, including MFIN (Microfinance), Sa-Dhan (Microfinance), FACE (Fintech), and FIDC (NBFC).
- SRPA की मान्यता के साथ, वित्तीय क्षेत्र में RBI द्वारा मान्यता प्राप्त कई SROs हो गए हैं : MFIN (माइक्रोफाइनेंस), Sa-Dhan (माइक्रोफाइनेंस), FACE (फिनटेक), और FIDC (एनबीएफसी)।

Ques: NPCI International Payments Limited (NIPL) recently partnered with which company to enable real-time cross-border remittances between India and Bahrain?

भारत और बहरीन के बीच वास्तविक समय में सीमा पार रेमिटेंस सक्षम करने के लिए NPCI International Payments Limited (NIPL) ने हाल ही में किस कंपनी के साथ साझेदारी की?

- A) PayPal / पेपैल
- B) Ripple / रिपल
- C) Western Union / वेस्टर्न यूनियन
- D) TransferWise / ट्रांसफरवाइज
- E) BENEFIT / बेनेफिट

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- NPCI International Payments Limited (NIPL) has entered into a strategic partnership with BENEFIT, a leading fintech and electronic financial transactions company in Bahrain, to facilitate real-time cross-border remittances between India and Bahrain.
- NPCI International Payments Limited (NIPL) ने भारत और बहरीन के बीच वास्तविक समय में सीमा पार रेमिटेंस को सक्षम करने के लिए बहरीन की प्रमुख फिनटेक और इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेनदेन कंपनी BENEFIT के साथ रणनीतिक साझेदारी की है।
- Under this collaboration, India's Unified Payments Interface (UPI) will be connected with Bahrain's Electronic Fund Transfer System (EFTS), specifically

the Fawri+ service, allowing users to send and receive money instantly and securely.

- इस सहयोग के तहत, भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) बहरीन के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम (EFTS), विशेष रूप से Fawri+ सेवा से जुड़ जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता तुरंत और सुरक्षित रूप से धन भेज और प्राप्त कर सकेंगे।
- The partnership is guided by the Reserve Bank of India (RBI) and the Central Bank of Bahrain (CBB).
- यह साझेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और बहरीन सेंट्रल बैंक (CBB) के मार्गदर्शन में स्थापित की गई है।

Ques: RBI's new rules allowing loans against silver will come into effect from which date?

RBI के नए नियम, जिनमें चांदी के बदले लोन की अनुमति दी गई है, किस तारीख से लागू होंगे?

- A) April 1, 2025
- B) April 1, 2026
- C) January 1, 2026
- D) March 31, 2026
- E) None of the above

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has announced that loans against silver will be permitted from April 1, 2026, in addition to existing loans against gold.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से सोने के साथ-साथ चांदी के बदले भी लोन लेने की अनुमति दी जाएगी।
- Individuals can pledge silver jewellery or coins to avail loans from banks, NBFCs, urban and rural co-operative banks, and housing finance companies.
- इसके तहत व्यक्ति चांदी के आभूषण या सिक्के गिरवी रखकर बैंकों, NBFCs, शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों तथा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से लोन ले सकेंगे।
- The Loan-to-Value (LTV) ratio will be up to 85% for loans up to ₹2.5 lakh, 80% for ₹2.5–5 lakh, and 75% for loans above ₹5 lakh.
- लोन-टू-वैल्यू (LTV) अनुपात ₹2.5 लाख तक के लोन पर 85%, ₹2.5–5 लाख के लोन पर

80%, और ₹5 लाख से ऊपर के लोन पर 75% होगा।

Ques: As per SEBI's latest reforms, what is the new minimum number of constituents required in the Nifty Bank index (BANKNIFTY)?

सेबी के नवीनतम सुधारों के अनुसार, निफ्टी बैंक इंडेक्स (BANKNIFTY) में अब न्यूनतम कितने अवयव आवश्यक होंगे?

- A) 10
- B) 11
- C) 12
- D) 13
- E) 14

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Securities and Exchange Board of India (SEBI) has introduced major reforms for the Nifty Bank index and other Non-Benchmark Indices (NBI) such as BANKNIFTY (NSE), BANKEX (BSE), and FINNIFTY (NSE).
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निफ्टी बैंक इंडेक्स और अन्य गैर-बेचमार्क सूचकांकों (BANKNIFTY, BANKEX, FINNIFTY) के लिए महत्वपूर्ण सुधार पेश किए हैं।
- As per the revised norms, the minimum number of constituents has been increased from 12 to 14.
- संशोधित मानदंडों के अनुसार, अवयवों की न्यूनतम संख्या 12 से बढ़ाकर 14 कर दी गई है।
- The weight of the top constituent is now capped at 20%, reduced from 33%, and the combined weight of the top three constituents has been lowered to 45% from 62%.
- शीर्ष अवयव का अधिकतम भार 33% से घटाकर 20% कर दिया गया है, और शीर्ष तीन अवयवों का संयुक्त भार 62% से घटाकर 45% कर दिया गया है।
- The index must follow a descending weight structure, meaning each stock's weight should be lower than the one above it.
- सूचकांक में अवरोही भार संरचना का पालन अनिवार्य होगा, जिसमें प्रत्येक स्टॉक का भार उससे ऊपर वाले स्टॉक से कम होना चाहिए।
- BANKEX and FINNIFTY must comply in a single phase by 31 December 2025, while BANKNIFTY has been given phased implementation until 31 March 2026.

- BANKEX और FINNIFTY को 31 दिसंबर 2025 तक एक ही चरण में अनुपालन करना होगा, जबकि BANKNIFTY को 31 मार्च 2026 तक चरणबद्ध रूप से लागू करने की अनुमति दी गई है।
- As of November 2025, Nifty Bank constituents include IDFC First Bank, Canara Bank, Punjab National Bank, Federal Bank, Bank of Baroda, State Bank of India, AU Small Finance Bank, Axis Bank, IndusInd Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, and Kotak Mahindra Bank.
- नवंबर 2025 तक, निफ्टी बैंक के अवयवों में IDFC फर्स्ट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं।

Ques: Which insurance company partnered with the International Finance Corporation (IFC) to promote inclusive life insurance services in India?
भारत में समावेशी जीवन बीमा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस बीमा कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम) IFC) के साथ साझेदारी की?

- A) LIC / एलआईसी
- B) HDFC Life Insurance / एचडीएफसी लाइफ इश्योरेंस
- C) Axis Max Life Insurance / एक्सिस मैक्स लाइफ इश्योरेंस
- D) ICICI Prudential Life Insurance / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इश्योरेंस
- E) SBI Life Insurance / एसबीआई लाइफ इश्योरेंस

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Axis Max Life Insurance Limited partnered with the International Finance Corporation (IFC), the lending arm of the World Bank, to promote inclusive life insurance services in India.
- एक्सिस मैक्स लाइफ इश्योरेंस लिमिटेड ने भारत में समावेशी जीवन बीमा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक के ऋण प्रभाग, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम) IFC) के साथ साझेदारी की।
- As part of the partnership, IFC invested Rs. 285 crores (approx. USD 33 million) in Axis Max Life Insurance through long-dated subordinated debt

instruments to strengthen the insurer's solvency ratio.

- साझेदारी के तहत, IFC ने लंबी अवधि वाले उपसर्गीय ऋण उपकरणों के माध्यम से एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 285 करोड़ रुपये) लगभग 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर (का निवेश किया, जिससे बीमाकर्ता का सॉल्वेंसी अनुपात मजबूत होगा।
- This initiative aligns with India's vision of "Insurance for All by 2047".
- यह पहल भारत की "2047 तक सभी के लिए बीमा" की दृष्टि के अनुरूप है।

About Axis Max Life Insurance :

- Established : 2001
- HQ : New Delhi
- MD & CEO : Sumit Madan

Ques: Which minister launched the mobile applications Sahakar Digi Pay and Sahakar Digi Loan to modernize urban cooperative banks in India?

भारत में शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिक बनाने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन Sahakar Digi Pay और Sahakar Digi Loan किस मंत्री ने लॉन्च किए?

- A) Finance Minister / वित्त मंत्री
- B) Minister of Finance and Corporate Affairs / वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री
- C) Minister of Electronics & IT / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
- D) Minister of Micro, Small & Medium Enterprises / सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
- E) Union Cooperation Minister / केंद्रीय सहयोग मंत्री

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Union Cooperation Minister Amit Shah launched two mobile applications — Sahakar Digi Pay and Sahakar Digi Loan — to modernize urban cooperative banks (UCBs) in India.
- केंद्रीय सहयोग मंत्री अमित शाह ने भारत में शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को आधुनिक बनाने के लिए दो मोबाइल एप्लिकेशन — Sahakar Digi Pay और Sahakar Digi Loan — लॉन्च किए।

- Sahakar Digi Pay is a digital payment platform for seamless transactions, while Sahakar Digi Loan is a digital lending platform facilitating easier credit access for individuals and small businesses.
- Sahakar Digi Pay लेनदेन को सहज बनाने वाला डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है, जबकि Sahakar Digi Loan व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए आसान ऋण सुविधा प्रदान करने वाला डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म है।
- The initiative aims to onboard 1,500 banks within two years and establish at least one additional UCB in every town with a population over 2 lakh within five years.
- इस पहल का लक्ष्य दो वर्षों में 1,500 बैंकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना और पांच वर्षों में प्रत्येक 2 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में कम से कम एक अतिरिक्त UCB स्थापित करना है।
- NAFCUB (National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Ltd.) will manage the rollout with technical support from NABARD.
- इस कार्यान्वयन को NAFCUB प्रबंधित करेगा, जिसमें NABARD तकनीकी समर्थन प्रदान करेगा।

Ques: Retail inflation in India fell to what historic low in October 2025?
अक्टूबर 2025 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति किस ऐतिहासिक स्तर तक गिर गई?

- A) 0.50%
- B) 0.40%
- C) 0.25%
- D) 0.75%
- E) None of the Above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Retail inflation dropped to a record low of 0.25% in October 2025.
- अक्टूबर 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर रिकॉर्ड 0.25% पर पहुंच गई।
- The fall was driven by GST rate cuts, favourable base effect, and reduced food inflation, especially in vegetables and fruits.
- GST दरों में कटौती, अनुकूल बेस इफेक्ट और सब्जियों व फलों में कम खाद्य मुद्रास्फीति के

कारण गिरावट दर्ज की गई।

- This is the lowest retail inflation rate recorded in the current CPI series.
- यह वर्तमान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) श्रृंखला में दर्ज की गई सबसे कम मुद्रास्फीति दर है।
- It is also the lowest inflation rate since January 2012.
- यह जनवरी 2012 के बाद दर्ज की गई सबसे कम दर है।
- The decline was mainly due to the statistical impact of the base effect on food inflation.
- कुल गिरावट मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति पर बेस इफेक्ट के सांख्यिकीय प्रभाव के कारण हुई।

Ques: Which two NBFCs had their Certificate of Registration cancelled by the RBI under Section 45-IA (6) of the RBI Act, 1934?

RBI ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत किस दो NBFCs का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया?

- A) Jumbo Finvest (India) Limited & Champion Agro Finance Limited / जम्बो फिनवेस्ट लिमि (इंडिया)टेड और चैंपियन एग्रो फाइनेंस लिमिटेड
- B) Parichay Commotrade Pvt Ltd & Renuka Investments and Finance Limited / परिचय कमोट्रेड प्रालिमिटेड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स रेनुका और .लि .
- C) Muthoot Finance & Manappuram Finance / मुत्थूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस
- D) SBI Cards & HDFC Credila / SBI कार्ड्स और HDFC क्रेडिला
- E) Bajaj Finance & L&T Finance / बजाज फाइनेंस और L&T फाइनेंस

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India, exercising powers under Section 45-IA (6) of the RBI Act, 1934, cancelled the Certificate of Registration of Jumbo Finvest (India) Limited, Jaipur, Rajasthan, and Champion Agro Finance Limited, Rajkot, Gujarat.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत जम्बो फिनवेस्ट (इंडिया)लिमिटेड (, जयपुर, राजस्थान और चैंपियन एग्रो फाइनेंस लिमिटेड, राजकोट, गुजरात का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया।

- Additionally, some NBFCs like Parichay Commotrade Pvt Ltd (Mumbai) and Renuka Investments and Finance Limited (UP) voluntarily surrendered their registration certificates.
- इसके अतिरिक्त, मुंबई स्थित परिचय कमोट्रेड प्रा रेनुका की प्रदेश उत्तर और .लि . जैसी लिमिटेड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स NBFCs ने स्वेच्छा से अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंपा।

Ques: Who chaired the review meeting with Managing Directors and CEOs of Public Sector Banks to assess H1 FY 2025–26 performance?

हाफ़ ईयर-FY 2025–26 के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और CEO के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की?

- A) Union Finance Minister / केंद्रीय वित्त मंत्री
- B) RBI Governor / आरबीआई गवर्नर
- C) Chairman, SBI / SBI के अध्यक्ष
- D) Secretary, Department of Financial Services / वित्तीय सेवाएँ विभाग के सचिव
- E) Secretary, Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय के सचिव

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Shri M. Nagaraju, Secretary of the Department of Financial Services (DFS), chaired a review meeting in New Delhi with the Managing Directors and Chief Executive Officers of Public Sector Banks to assess their performance for H1 FY 2025–26.
- श्री एमनगराजू ., वित्तीय सेवाएँ विभाग)DFS) के सचिव, ने नई दिल्ली में पब्लिक सेक्टर बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और CEO के साथ हाफ़ ईयर-FY 2025–26 के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
- During H1 FY 2025–26, PSBs reported a net profit of ₹93,675 crore, advances grew by 12.3%, deposits by 9.6%, Gross NPA ratio declined to 2.30%, and Net NPA to 0.45%.
- हाफ़ ईयर-FY 2025–26 के दौरान, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने ₹93,675 करोड़ का शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया, अग्रिम राशि में 12.3% की वृद्धि, जमा में 9.6% की वृद्धि, सकल एनपीए अनुपात 2.30% और शुद्ध एनपीए 0.45% तक गिर गया।

- The meeting also included the launch of the Startup Loans module on JanSamarth Portal and the release of the PSB Manthan 2025 report.
- बैठक में JanSamarth पोर्टल पर स्टार्टअप लोन मॉड्यूल का लॉन्च और PSB Manthan 2025 रिपोर्ट जारी करने का भी कार्यक्रम शामिल था।

Ques: Which bank launched the cultural initiative 'Bharat Surotsav' in Chennai?

किस बैंक ने चेन्नई में सांस्कृतिक पहल 'भारत सुरोत्सव' की शुरुआत की?

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) Federal Bank / फेडरल बैंक
- D) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- E) Axis Bank / एक्सिस बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Federal Bank Limited launched 'Bharat Surotsav' in Chennai, marking the beginning of its festival series celebrating India's artistic heritage.
- फेडरल बैंक लिमिटेड ने चेन्नई में 'भारत सुरोत्सव' की शुरुआत की, जो भारत की कला और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने वाली फेस्टिवल श्रृंखला की शुरुआत है।
- Bharat Surotsav is an immersive dance and music fusion festival and a signature cultural Intellectual Property (IP) of Federal Bank, featuring artists like Shobana Chandrakumar Pillai, Agam Band, Charumathi Raghuraman, and Ravi Chari.
- भारत सुरोत्सव एक इमर्सिव डांस और म्यूजिक फ्यूजन फेस्टिवल है और फेडरल बैंक की प्रमुख सांस्कृतिक बौद्धिक संपदा (IP) है, जिसमें शोभना चंद्रकुमार पिल्लै, अगम बैंड, चारुमथी रघुरामन और रवि चारी जैसे कलाकार शामिल हैं।

About Federal Bank :

- Established : 1931
- HQ : Kochi, Kerala

- MD & CEO : KVS Manian
 - Tagline : Your Perfect Banking Partner
-

Ques: RBI increased the maximum credit period for pre- and post-shipment export credit to how many days?

**RBI ने प्री शिपमेंट-पोस्ट शिपमेंट-पोस्ट और -
है?**

- A) 270 days
- B) 300 days
- C) 360 days
- D) 450 days
- E) 500 days

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) announced a major export relief package to support exporters affected by the 50% US tariff on Indian exports.
- अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने से प्रभावित निर्यातकों के लिए RBI ने बड़ी राहत पैकेज की घोषणा की।
- Under the package, the maximum credit period for pre- and post-shipment export credit has been enhanced from 270 days to 450 days for loans disbursed till 31 March 2026.
- इस पैकेज के तहत 31 मार्च 2026 तक वितरित प्री शिपमेंट-पोस्ट और - अवधि अधिकतम 270 दिनों से बढ़ाकर 450 दिन कर दी गई है।
- Lenders can liquidate packing credit through any legitimate source for exporters who could not dispatch goods by 31 August 2025.
- ऐसे निर्यातकों के लिए जो 31 अगस्त 2025 तक सामान भेज नहीं पाए, बैंक अब पैकिंग क्रेडिट किसी भी वैध स्रोत से निपटा सकते हैं।
- RBI allowed moratorium or deferment on term-loan repayments and interest recovery on working capital loans due between 1 September–31 December 2025.
- RBI ने 1 सितंबर–31 दिसंबर 2025 के बीच देय टर्म कैपिटल वर्किंग और भुगतान लोन-दी। अनुमति की स्थगन/मोरेटोरियम पर ब्याज

- Banks can recalculate drawing power in working capital loans by reducing margins or reassessment.
- बैंक वर्किंग कैपिटल में मार्जिन कम करके या पुनः मूल्यांकन करके ड्रॉइंग पावर फिर से निर्धारित कर सकते हैं।
- The time limit for realisation and repatriation of export proceeds has been extended from 9 months to 15 months, and the shipment period against advance payment increased from 1 year to 3 years.
- निर्यात आय की वसूली और वापसी की समयसीमा 9 महीने से बढ़ाकर 15 महीने कर दी गई है, और अग्रिम भुगतान पर माल भेजने की समयसीमा 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है।
- These measures aim to reduce the financial burden on exporters and ensure business continuity amid global trade disruptions.
- इन उपायों का उद्देश्य निर्यातकों पर वित्तीय बोझ कम करना और वैश्विक व्यापार व्यवधानों के बीच व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करना है।

Ques: According to the PLFS Quarterly Bulletin (July–September 2025), what was India’s unemployment rate for persons aged 15 years and above in Q2 FY26?

PLFS त्रैमासिक बुलेटिन (जुलाई)–सितंबर 2025) के अनुसार, Q2 FY26 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर क्या थी?

- A) 4.4%
- B) 5.2%
- C) 5.4%
- D) 6.8%
- E) 8.9%

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The National Statistical Office (NSO), under the Ministry of Statistics and Programme Implementation, released the Periodic Labour Force Survey (PLFS) Quarterly Bulletin for July–September 2025.
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने जुलाई–सितंबर 2025 के लिए आवधिक श्रमिक बल सर्वेक्षण (PLFS) त्रैमासिक बुलेटिन जारी किया।

- India's unemployment rate for persons aged 15 years and above declined to 5.2% in Q2 FY26, down from 5.4% in Q1 FY26.
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर Q2 FY26 में घटकर 5.2% रही, जो Q1 FY26 में 5.4% थी।
- Rural unemployment fell from 4.8% to 4.4%, while urban unemployment rose slightly from 6.8% to 6.9%.
- ग्रामीण बेरोजगारी 4.8% से घटकर 4.4% हो गई, जबकि शहरी बेरोजगारी 6.8% से बढ़कर 6.9% हो गई।
- Uttarakhand recorded the highest unemployment rate at 8.9%, followed by Andhra Pradesh (8.2%) and Kerala (8%).
- उत्तराखंड ने सबसे अधिक बेरोजगारी दर 8.9% दर्ज की, इसके बाद आंध्र प्रदेश (8.2%) और केरल (8%) रहे।
- Labour Force Participation Rate (LFPR) for persons aged 15+ increased slightly from 55% to 55.1%.
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का श्रम बल सहभागिता दर 55% से बढ़कर 55.1% हो गया।
- Female participation rose from 33.4% to 33.7%, while male participation declined slightly from 77.3% to 77.2%.
- महिला सहभागिता 33.4% से बढ़कर 33.7% हुई, जबकि पुरुष सहभागिता 77.3% से घटकर 77.2% हो गई।
- Agriculture employed 42.4% of the workforce, the tertiary sector 33.5%, and the secondary sector including mining and quarrying 24.2%.
- कृषि क्षेत्र में 42.4% कार्यबल कार्यरत रहा, तृतीयक क्षेत्र में 33.5%, और द्वितीयक क्षेत्र में (सहित उत्खनन और खनन) 24.2% कार्यरत रहे।

Ques: Which three key surveys were launched by the Reserve Bank of India in November 2025?

नवंबर 2025 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कौनगए किए शुरू सर्वेक्षण प्रमुख तीन से-?

- Industrial Outlook Survey, Udyog Survey, Banking Trend Survey
- Inflation Expectations Survey of Households, Rural Consumer Confidence Survey, Urban Consumer Confidence Survey
- Household Debt Survey, Labour Force Survey, Urban Market Survey
- Price Stability Survey, Rural Income Survey, City Demand Survey
- Monetary Outlook Survey, Employment Sentiment Survey, Household Spending Survey

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India launched three key surveys for November 2025: Inflation Expectations Survey of Households (IESH), Rural Consumer Confidence Survey (RCCS), and Urban Consumer Confidence Survey (UCCS).
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2025 के लिए तीन प्रमुख सर्वेक्षण शुरू किए: इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेडेंस सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स (IESH), रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे (RCCS) और अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे (UCCS)।
- These surveys provide essential inputs for monetary policy formulation.
- ये सर्वेक्षण मौद्रिक नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
- IESH collects households' perceptions on price movements and inflation across 19 major Indian cities.
- IESH 19 प्रमुख भारतीय शहरों में कीमतों में उतार की परिवारों पर मुद्रास्फीति और चढ़ाव-है। करता एकत्र धारणा
- RCCS is a bi-monthly survey capturing rural and semi-urban household views on economic situation, employment, prices, income and spending across 31 States/UTs.
- RCCS एक द्विमासिक सर्वेक्षण है, जो 31 राज्यों-अर्ध और ग्रामीण में प्रदेशों शासित केंद्र/स्थिति आर्थिक की परिवारों शहरी, रोजगार, कीमतें, आय और खर्च पर राय एकत्र करता है।
- UCCS is also bi-monthly and gathers urban consumer sentiments on economy, employment, income, spending and price trends across 19 cities.
- UCCS भी द्विमासिक है और 19 शहरों में शहरी परिवारों से अर्थव्यवस्था, रोजगार, आय, खर्च और कीमतों के रुझान पर विचार एकत्र करता है।

Ques: What was the annual credit growth of banks at the end of October 31, 2025?

31 अक्टूबर, 2025 को बैंकों की वार्षिक क्रेडिट वृद्धि कितनी थी?

- A) 9.7%
- B) 10.5%
- C) 11.3%
- D) 12.0%
- E) 13.5%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- According to Reserve Bank of India data, banks' annual credit growth at the end of October 31, 2025, stood at 11.3%, while deposits grew 9.7%.
 - भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 को बैंकों की वार्षिक क्रेडिट वृद्धि 11.3% रही, जबकि जमा राशि 9.7% बढ़ी।
 - The gap between credit and deposit growth narrowed to 160 basis points from 200 basis points observed on October 17.
 - 17 अक्टूबर को 200 आधार अंक के मुकाबले क्रेडिट और जमा वृद्धि के बीच का अंतर 160 आधार अंक तक घट गया।
 - Demand deposits rose 21% year-on-year to Rs 31 lakh crore, reflecting faster growth in low-cost current and savings deposits.
 - डिमांड डिपॉज़िट्स में 21% की वार्षिक वृद्धि हुई और यह 31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो कम लागत वाले चालू और बचत खातों में तेजी से वृद्धि को दर्शाता है।
 - Time deposits (fixed deposits) grew 8.3% to Rs 211 lakh crore.
 - टाइम डिपॉज़िट्स (डिपॉज़िट्स फिक्स्ड) 8.3% बढ़कर 211 लाख करोड़ रुपये हो गए।
-

Ques: Which bank celebrated its 107th foundation day and inaugurated 51 new branches virtually?

किस बैंक ने अपना 107वां स्थापना दिवस मनाया और 51 नई शाखाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया?

- A) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- D) Bank of Baroda / बैंक ऑफ़ बड़ौदा
- E) Canara Bank / कैनरा बैंक

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Union Bank of India celebrated its 107th foundation day at the Jio World Convention Centre, BKC, Mumbai, Maharashtra.
- यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ने मुंबई, महाराष्ट्र के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, BKC में अपना 107वां स्थापना दिवस मनाया।
- The bank inaugurated 51 new branches virtually across key regions and a Rural Self-Employment Training Institute (RSETI) in Mancherial, Telangana.
- बैंक ने प्रमुख क्षेत्रों में 51 नई शाखाओं और तेलंगाना के मांचीरील में एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) का वर्चुअल उद्घाटन किया।
- Union Bank employees contributed Rs 21.68 crore to the National Defence Fund (NDF), supporting India's armed forces.
- यूनियन बैंक के कर्मचारियों ने राष्ट्रीय रक्षा कोष (NDF) में 21.68 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जिससे देश की सशस्त्र सेनाओं का समर्थन हुआ।
- The bank also launched two new digital products: Union eBiz, a business mobile application for MSMEs and business customers with 20+ journeys and 300+ features, and Union Ease, a retail app to be available soon.
- बैंक ने दो नए डिजिटल उत्पाद भी लॉन्च किए : Union eBiz, MSMEs और व्यापार ग्राहकों के लिए 20+ जर्नी और 300+ फीचर्स वाला व्यवसाय मोबाइल एप, और Union Ease, एक रिटेल एप जो जल्द ही उपलब्ध होगा।

About Union Bank of India :

- Established : 1919
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Shri Asheesh Pandey
- Tagline : Good people to bank with

Ques: Who has been appointed as the Part-Time Chairman of Jammu & Kashmir (J&K) Bank Limited?

जम्मू और कश्मीर (J&K) बैंक लिमिटेड के पार्ट टाइम नियुक्त किसे में रूप के चेयरमैन टाइम-है गया?

- A) Amitava Chatterjee / अमितावा चटर्जी
- B) S Krishnan / एस कृष्णन
- C) Rajesh Kumar / राजेश कुमार
- D) Sunil Mehta / सुनील मेहता
- E) P K Gupta / पी के गुप्ता

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- S Krishnan has been appointed as the Part-Time Chairman of Jammu & Kashmir (J&K) Bank Limited for the tenure November 13, 2025, to March 26, 2028.
 - एस कृष्णन को जम्मू और कश्मीर (J&K) बैंक लिमिटेड के पार्ट में रूप के चेयरमैन टाइम-13 नवंबर 2025 से 26 मार्च 2028 तक के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है।
 - He previously served as Managing Director & CEO of Punjab & Sind Bank (2020–2022) and Tamilnad Mercantile Bank (2022–2024).
 - उन्होंने पहले पंजाब और सिंध बैंक (2020–2022) और तमिलनाडु मर्चेन्टाइल बैंक (2022–2024) में प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्य किया।
 - J&K Bank was established in 1938, headquartered in Srinagar, Jammu & Kashmir.
 - J&K बैंक की स्थापना 1938 में हुई थी, इसका मुख्यालय श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में है।
 - The current MD & CEO of J&K Bank is Amitava Chatterjee.
 - J&K बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ अमितावा चटर्जी हैं।
-

Ques: What GDP growth projection has India Ratings and Research (Ind-Ra) made for India in Q2 FY26?

भारत रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए भारत की GDP वृद्धि के बारे में क्या अनुमान लगाया है?

- A) 5.6%
- B) 6.4%
- C) 7.2%
- D) 7.8%
- E) 8.0%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- India Ratings and Research (Ind-Ra) has projected India's GDP growth at 7.2% for the second quarter of FY26, which is higher than Q2FY25's 5.6% but lower than Q1FY26's 7.8%.
- भारत रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए भारत की GDP वृद्धि 7.2% अनुमानित की है, जो Q2FY25 में दर्ज 5.6% से अधिक है, लेकिन Q1FY26 के 7.8% से कम है।
- Ind-Ra also noted that India's nominal GDP growth may have slipped below 8% year-on-year in Q2FY26.
- Ind-Ra ने यह भी संकेत दिया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की नाममात्र GDP वृद्धि 8% वर्ष-दर-वर्ष से नीचे जा सकती है।

Ques: Which fintech platform received RBI approval to operate as a payment aggregator?

किस फिनटेक प्लेटफॉर्म को RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दी है?

- A) Razorpay / रेज़रपे
- B) Paytm / पेटीएम
- C) CCAvenue / सीसीएवेन्यू
- D) PayU / PayU
- E) PhonePe / फोनपे

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- PayU has received integrated authorisation from the Reserve Bank of India (RBI) to operate as a payment aggregator.
- PayU को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से इंटीग्रेटेड ऑथराइज़ेशन मिला है ताकि वह पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम कर सके।
- The licence enables PayU to handle online, offline (physical), and cross-border transactions, including inward and outward payments.
- यह लाइसेंस PayU को ऑनलाइन, ऑफलाइन (फिजिकल) और क्रॉस-बॉर्डर ट्रांज़ैक्शंस, जिनमें "इनवर्ड और आउटवर्ड" भुगतान शामिल हैं, को संभालने की अनुमति देता है।
- Approval is granted under the Payment and Settlement Systems (PSS) Act, allowing seamless payment acceptance, settlement, and cross-border solutions

for merchants.

- यह मंजूरी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स) PSS) एक्ट के तहत दी गई है और व्यापारियों के लिए सहज भुगतान स्वीकृति, सेटलमेंट और क्रॉस-बॉर्डर समाधान उपलब्ध कराएगी।

Ques: Which bank organised the 10th edition of EVOLVE, a knowledge series for MSMEs, in Kozhikode, Kerala?

कोझिकोड, केरल में एमएसएमई के लिए EVOLVE की 10वीं संस्करण का आयोजन किस बैंक ने किया?

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Axis Bank Limited organised the 10th edition of EVOLVE, its flagship multi-city knowledge series for Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs), in Kozhikode, Kerala.
- एक्सिस बैंक लिमिटेड ने कोझिकोड, केरल में अपने प्रमुख बहु-शहर ज्ञान श्रृंखला EVOLVE के 10वें संस्करण का आयोजन किया, जो माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों) MSMEs) के लिए है।
- Themed “MSMEs Powering the USD 10 Trillion Economy”, the session gathered 100+ entrepreneurs and experts to discuss opportunities and challenges shaping India’s growth from USD 4.1 trillion to USD 10 trillion by 2032.
- “MSMEs Powering the USD 10 Trillion Economy” थीम के तहत इस सत्र में 100+ उद्यमियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया, और 2032 तक भारत की आर्थिक वृद्धि को USD 4.1 ट्रिलियन से USD 10 ट्रिलियन तक ले जाने वाले अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की।
- The EVOLVE initiative aims to empower MSMEs with tools to enhance operational efficiency, adopt digital solutions, and expand market reach.
- EVOLVE पहल का उद्देश्य MSMEs को संचालन क्षमता बढ़ाने, डिजिटल समाधान अपनाने,

और बाजार पहुँच का विस्तार करने के उपकरण प्रदान करना है।

About Axis Bank :

- Established : 1993
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- Chairman : Rakesh Makhija
- MD & CEO : Amitabh Chaudhary
- Tagline : Badhti Ka naam Zindagi

Ques: Which bank became the first lender to put its ₹511 crore exposure to Lavasa Corp up for sale?

कौन सा बैंक अपने ₹511 करोड़ के Lavasa Corp एक्सपोज़र को बिक्री के लिए रखने वाला पहला ऋणदाता बना?

- A) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- D) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Axis Bank became the first lender to put its ₹511 crore exposure to Lavasa Corp up for sale at a reserve price of ₹80 crore.
- एक्सिस बैंक अपने ₹511 करोड़ के Lavasa Corp एक्सपोज़र को ₹80 करोड़ आरक्षित मूल्य पर बिक्री के लिए रखने वाला पहला बैंक बना।
- The bank invited Expressions of Interest (EOIs) from Asset Reconstruction Companies (ARCs), NBFCs, and financial institutions, with submissions due by November 18, 2025, and an e-auction scheduled for November 21, 2025.
- बैंक ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs), एनबीएफसी और वित्तीय संस्थानों से अभिरुचि प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2025 और ई-नीलामी 21 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई।

- Lavasa Corp's bankruptcy case has been ongoing since 2018, with creditors led by Union Bank of India facing challenges due to environmental clearances and unresolved legal issues.
- Lavasa Corp का दिवालियापन मामला 2018 से चल रहा है, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले लेनदारों को पर्यावरणीय मंजूरी और अनसुलझे कानूनी मुद्दों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- Lavasa owes creditors a total of ₹6,642 crore.
- Lavasa अपने लेनदारों को कुल ₹6,642 करोड़ का बकाया है।

Ques: When will the mCASH sending and claiming facility on OnlineSBI and YONO Lite be discontinued by SBI?

एसबीआई द्वारा OnlineSBI और YONO Lite पर mCASH भेजने और दावा करने की सुविधा कब बंद की जाएगी?

- A) 15 November 2025
- B) 30 November 2025
- C) 1 December 2025
- D) 31 December 2025
- E) 1 January 2026

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) announced that the mCASH sending and claiming facility on OnlineSBI and YONO Lite platforms will be discontinued on 30 November 2025, and the service will be unavailable from 1 December 2025.
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने घोषणा की कि OnlineSBI और YONO Lite प्लेटफॉर्म पर mCASH भेजने और दावा करने की सुविधा 30 नवंबर 2025 को बंद कर दी जाएगी, और 1 दिसंबर 2025 से यह सेवा उपलब्ध नहीं होगी।
- The discontinuation reflects SBI's shift toward more secure, modern, and widely adopted digital payment systems.
- इस सेवा बंद करने का उद्देश्य SBI के अधिक सुरक्षित, आधुनिक और व्यापक रूप से अपनाए गए डिजिटल भुगतान प्रणाली की ओर बदलाव को दर्शाता है।
- The service allowed instant transfers using only the recipient's mobile number or email ID, without requiring beneficiary registration.

- यह सुविधा केवल प्राप्तकर्ता के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करके तत्काल पैसे भेजने की अनुमति देती थी, बिना लाभार्थी पंजीकरण के।
 - SBI has advised customers to use other secure digital payment options such as UPI, IMPS, NEFT, and RTGS for third-party transfers.
 - SBI ने ग्राहकों से तीसरे पक्ष को पैसे भेजने के लिए UPI, IMPS, NEFT, और RTGS जैसी अन्य सुरक्षित डिजिटल भुगतान विकल्पों का उपयोग करने की सलाह दी है।
-

**Ques: What real GDP growth has SBI projected for India in Q2 FY26?
SBI ने Q2 FY26 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि कितनी अनुमानित की है?**

- A) 6.5%
- B) 7.0%
- C) 8.0%
- D) 7.8%
- E) 7.5%

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- SBI's Economic Research Department (ERD) has projected India's real GDP growth at 7.5% in Q2 FY26, with potential for an upside.
- SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग (ERD) ने Q2 FY26 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 7.5% रहने का अनुमान लगाया है, और इसे बढ़कर आने की संभावना भी बताई है।
- Growth is supported by higher investment activities, rural demand recovery, buoyancy in services and manufacturing, and GST rationalisation.
- निवेश गतिविधियों में वृद्धि, ग्रामीण मांग के सुधार, सेवाओं व विनिर्माण में तेजी और GST तर्कसंगतीकरण से वृद्धि को समर्थन मिल रहा है।
- India's Q1 FY26 GDP grew 7.8%, a five-quarter high, compared to 6.5% in Q1 FY25.
- भारत की Q1 FY26 GDP 7.8% रही, जो पिछले पाँच तिमाहियों में सबसे अधिक है, जबकि Q1 FY25 में यह 6.5% थी।
- Leading indicators for consumption, agriculture, industry, and services demand rose to 83% in Q2 from 70% in Q1.
- उपभोग, कृषि, उद्योग और सेवा मांग के अग्रणी संकेतक Q1 के 70% से बढ़कर Q2 में 83%

हो गए।

- Credit card spending reached ₹6,400 crore on Sept 23 and ₹7,328 crore on Diwali, reflecting strong festival demand.
- 23 सितंबर को ₹6,400 करोड़ और दिवाली पर ₹7,328 करोड़ का क्रेडिट कार्ड खर्च दर्ज हुआ — जो मजबूत त्योहार मांग को दर्शाता है।
- Debit card spends rose highest in Haryana (20%), Telangana (19%), and Andhra Pradesh (19%).
- डेबिट कार्ड खर्च) हरियाणा :20%), तेलंगाना)19%), आंध्र प्रदेश)19%) में सबसे अधिक वृद्धि हुई।
- Gross domestic GST collections for November 2025 are estimated at ₹1.49 lakh crore with YoY growth of 6.8%.
- नवंबर 2025 के घरेलू GST संग्रह ₹1.49 लाख करोड़ रहने का अनुमान, सालाना वृद्धि 6.8%।

Ques: Which bank partnered with Kendriya Vidyalaya Sangathan to implement salary accounts and an integrated salary portal for KVS employees?

कौन सा बैंक केन्द्रीय विद्यालय संगठन के साथ साझेदारी में KVS कर्मचारियों के लिए सैलरी अकाउंट और एकीकृत सैलरी पोर्टल लागू कर रहा है?

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) Bank of Baroda / बैंक ऑफ़ बड़ौदा
- D) Canara Bank / कैनरा बैंक
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Union Bank of India has entered into a strategic partnership with Kendriya Vidyalaya Sangathan to implement salary accounts and an integrated salary portal for KVS employees across India.
- यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के साथ साझेदारी की है, ताकि पूरे

भारत में KVS कर्मचारियों के लिए सैलरी अकाउंट और एकीकृत सैलरी पोर्टल लागू किया जा सके।

- This collaboration will cover all 1,290 Kendriya Vidyalayas and support the salary management needs of nearly 56,000 employees.
- इस साझेदारी के तहत देश के सभी 1,290 केन्द्रीय विद्यालय शामिल होंगे और लगभग 56,000 कर्मचारियों की सैलरी प्रबंधन आवश्यकताओं का समर्थन किया जाएगा।

Ques: Who is the Chairman of the Sixteenth Finance Commission (XVIFC) for the period 2026–27 to 2030–31?

सोलहवें वित्त आयोग (XVIFC) के 2026–27 से 2030–31 की अवधि के लिए अध्यक्ष कौन हैं?

- A) Dr. Manoj Panda / डॉमनोज पांडा .
- B) Dr. Arvind Panagariya / डॉ अरविंद .पनगढ़िया
- C) T. Rabi Sankar / टीरबी शंकर .
- D) Dr. Soumyakanti Ghosh / डॉसौम्यकांति घोष .
- E) None / कोई नहीं

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Sixteenth Finance Commission (XVIFC) submitted its report to the President of India for the period 2026–27 to 2030–31.
- सोलहवें वित्त आयोग (XVIFC) ने 2026–27 से 2030–31 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की।
- XVIFC was constituted under Article 280(1) of the Constitution.
- XVIFC का गठन संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत किया गया था।
- Chairman: Dr. Arvind Panagariya; Members include Annie George Mathew, Dr. Manoj Panda, Shri T. Rabi Sankar, Dr. Soumyakanti Ghosh, and Secretary Ritvik Pandey.
- अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया .डॉ .; सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू ., डॉमनोज पांडा ., टीरबी शंकर ., डॉसौम्यकांति घोष और सचिव ऋत्विक् पांडे। .
- The Commission was mandated to give recommendations for a 5-year award period from 1 April 2026 to 31 March 2031.

- आयोग को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की 5-वर्षीय अवधि के लिए सिफारिशें देने का दायित्व दिया गया था।
- Mandate includes distribution of tax proceeds between Union & States, inter-state allocation, grants-in-aid, and financing arrangements for disaster management.
- मंडेट में शामिल केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का वितरण ;, राज्यों के बीच आवंटन, अनुदान, और आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय व्यवस्था।
- Report consists of two volumes — Volume I (Recommendations), Volume II (Annexures).
- रिपोर्ट दो बॉल्यूम में है — बॉल्यूम I (सिफारिशें), बॉल्यूम II (परिशिष्ट)।
- Report will be made public after it is tabled in Parliament under Article 281.
- रिपोर्ट संसद में अनुच्छेद 281 के तहत पेश किए जाने के बाद सार्वजनिक की जाएगी।
- The Sixteenth Finance Commission is headed by Dr. Arvind Panagariya.
- सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं।

Ques: Which company has received RBI's final authorisation to operate as an offline payment aggregator?

कौन सी कंपनी को ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की अंतिम मंजूरी मिली है?

- A) Razorpay / रेज़रपे
- B) Paytm / पेटीएम
- C) Infibeam Avenues / इंफीबीम एवेन्यूज़
- D) PhonePe / फोनपे
- E) CCAvenue / सीसीएवेन्यू

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Infibeam Avenues has received final regulatory authorisation from the Reserve Bank of India to operate as an offline payment aggregator, enabling it to handle in-store card and QR-based transactions via POS devices.
- इंफीबीम एवेन्यूज़ को ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की अंतिम मंजूरी मिली है, जिससे यह POS डिवाइस के माध्यम से स्टोर में कार्ड और QR-

आधारित लेनदेन को संभाल सकेगा।

- The company already holds licences for online payment aggregation, prepaid payment instruments (PPI), and Bharat Bill Pay.
- कंपनी के पास पहले से ही ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेशन, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI), और भारत बिल पे के लिए लाइसेंस मौजूद हैं।

Ques: Bank of Baroda (BoB) and which institution have signed an MoU to enhance credit flow and support for MSMEs and startups?

बैंक ऑफ बड़ौदा) BoB) ने MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए ऋण प्रवाह और समर्थन बढ़ाने हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया है?

- A) NABARD / नाबार्ड
- B) SIDBI / सिडबी
- C) EXIM Bank / एक्सिम बैंक
- D) RBI / भारतीय रिज़र्व बैंक
- E) IFCI / आईएफ़सीआई

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• Bank of Baroda (BoB) and the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) signed a Memorandum of Understanding (MoU) to enhance credit flow and working capital support for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and startups.

• बैंक ऑफ बड़ौदा) BoB) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) SIDBI) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) MSMEs) और स्टार्टअप्स के लिए ऋण प्रवाह और कार्यशील पूंजी समर्थन बढ़ाने हेतु एक समझौता (ज्ञापन) MoU) पर हस्ताक्षर किए।

• Under the partnership, both institutions will jointly finance MSMEs, enable SIDBI-sanctioned borrowers to use BoB's working capital platform, and provide customised solutions for export-oriented businesses.

• इस साझेदारी के तहत दोनों संस्थान संयुक्त रूप से MSMEs को वित्त प्रदान करेंगे, सिडबी द्वारा स्वीकृत उधारकर्ताओं को BoB के कार्यशील पूंजी प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने की सुविधा देंगे, और निर्यात-उन्मुख व्यवसायों के लिए अनुकूलित समाधान प्रदान करेंगे।

• The collaboration will strengthen startup support through SIDBI's Venture

Debt Programme and BoB's specialised Startup Banking services, including advisory and tailored financial products.

• यह सहयोग SIDBI के वेंचर डेब्ट कार्यक्रम और BoB की विशेष स्टार्टअप बैंकिंग सेवाओं— परामर्श और अनुकूलित वित्तीय उत्पादों सहित—के माध्यम से स्टार्टअप समर्थन को और मजबूत करेगा।

About Bank of Baroda :

- Established : 1908
- HQ : Vadodara, Gujarat
- Tagline : India's International Bank
- MD & CEO : Debadatta Chand

About SIDBI :

- Established : 1990
- HQ : Lucknow, Uttar Pradesh
- Chairman & MD : Manoj Mittal

Ques: Which bank launched the premium credit cards LUMIERE and NOVA to enter the high-end credit card segment?

किस बैंक ने प्रीमियम क्रेडिट कार्ड LUMIERE और NOVA लॉन्च करके उच्च क्रेडिट स्तरीय-किया प्रवेश में सेगमेंट कार्ड?

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B) RBL Bank / RBL बैंक
- C) ICICI Bank / ICICI बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• RBL Bank has launched two premium credit cards — LUMIERE and NOVA — marking its entry into the high-end credit card segment.

- RBL बैंक ने दो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड — LUMIERE और NOVA — लॉन्च किए, जो उच्च-हैं। करते चिह्नित को प्रवेश इसके में सेगमेंट कार्ड क्रेडिट स्तरीय
- The launch aims to target India's growing base of high-net-worth and affluent consumers seeking luxury-focused financial products.
- इस लॉन्च का उद्देश्य भारत के बढ़ते उच्च नेटवर-थ और संपन्न उपभोक्ताओं को लक्षित करना है, जो लक़्ज़री हैं। रहे कर तलाश की उत्पादों वित्तीय केंद्रित-
- LUMIÈRE card weighs 18 grams and comes with an annual fee of ₹50,000. NOVA is a metal card aimed at consumers prioritising reward-based value and lifestyle-linked features, with an annual fee of ₹12,500.
- LUMIÈRE कार्ड का वजन 18 ग्राम है और इसकी वार्षिक शुल्क ₹50,000 है। NOVA एक मेटल कार्ड है, जो उन उपभोक्ताओं के लिए है जो पुरस्कार आधारित मूल्य और जीवनशैली-हैं देते प्राथमिकता को सुविधाओं संबंधी, जिसकी वार्षिक शुल्क ₹12,500 है।

About RBL Bank Limited:

- Established : 1943
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- MD & CEO : R Subramaniakumar
- Tagline : Apno ka bank

Ques: Which bank was penalized ₹39.60 lakh by RBI for violating provisions of the PSS Act and BR Act?

किस बैंक को PSS अधिनियम और BR अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए RBI ने 39.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया?

- A) Tamilnad Mercantile Bank Limited / तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लिमिटेड
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- D) ICICI Bank / ICICI बैंक
- E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) imposed a penalty of ₹39.60 lakh on Tamilnad Mercantile Bank Limited.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर 39.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
- The penalty was for violating provisions of section 10A of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act) and section 26A of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act).
- यह जुर्माना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 (PSS अधिनियम धारा की (10A और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (BR अधिनियम धारा की (26A का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया।

Ques: How many new names did RBI add to its alert list of unauthorised forex trading platforms?

RBI ने अपने अनधिकृत विदेशी मुद्रा (Forex) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अलर्ट लिस्ट में कितने नए नाम जोड़े?

- A) 5
- B) 6
- C) 11
- D) 8
- E) 7

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) added 7 new names to its alert list of unauthorised forex trading platforms, taking the total number to 95.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपने अनधिकृत विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अलर्ट लिस्ट में 7 नए नाम जोड़े, जिससे कुल संख्या 95 हो गई।
- The alert list includes entities that are neither authorised under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) to deal in forex nor authorised to operate electronic trading platforms (ETP) for forex transactions.
- यह अलर्ट लिस्ट उन संस्थाओं के नामों को शामिल करती है जो विदेशी मुद्रा लेन लिए के देन-

अधिनियम प्रबंधन मुद्रा विदेशी, 1999 (FEMA) के तहत अधिकृत नहीं हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनके देन- लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ETP) संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।

- The newly added platforms are: Starnet FX, CapPlace, Mirrox, Fusion Markets, Trive, NXG Markets, and Nord FX.
- नए जोड़े गए प्लेटफॉर्म हैं :Starnet FX, CapPlace, Mirrox, Fusion Markets, Trive, NXG Markets, और Nord FX।

Ques: Bima Gram API, recently tested by IRDAI, is primarily designed to improve which of the following?

IRDAI द्वारा परीक्षण किया गया Bima Gram API मुख्य रूप से किसको बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है?

- A) Urban insurance marketing / शहरी बीमा विपणन
- B) Rural insurance penetration / ग्रामीण बीमा पैठ
- C) International reinsurance operations / अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमा संचालन
- D) Motor claim settlement / मोटर क्लेम निपटान
- E) Agriculture subsidy distribution / कृषि सब्सिडी वितरण

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Bima Gram API, launched by IRDAI, is designed to increase insurance penetration in rural markets.
- IRDAI द्वारा लॉन्च किया गया Bima Gram API ग्रामीण बाजारों में बीमा पैठ बढ़ाने के लिए बनाया गया डिजिटल टूल है।
- The API has successfully completed the pilot testing phase.
- इस API ने अपना पायलट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
- As part of the pilot, five insurers (two life, two general, and one health) integrated, tested, and verified the API functionalities.
- पायलट में 5 बीमा कंपनियों—2 जीवन, 2 सामान्य और 1 स्वास्थ्य बीमाकर्ता—ने API के functions को integrate, test और verify किया।
- The API enables digital validation and accurate mapping of rural policies with respective gram panchayats, reduces manual paperwork, and improves accuracy, speed, and efficiency in rural business reporting.

- Bima Gram API ग्रामीण नीतियों को डिजिटल रूप से मान्य, प्रमाणित और ग्राम पंचायतों के साथ सटीक रूप से मैप करने में मदद करेगा, मैनुअल दस्तावेज़ीकरण कम करेगा, और ग्रामीण व्यवसाय रिपोर्टिंग में सटीकता, गति और दक्षता बढ़ाएगा।
- The API helps insurers build comprehensive rural datasets for future policy planning and resource allocation.
- API बीमाकर्ताओं को भविष्य की नीति योजना और संसाधन आवंटन के लिए मजबूत ग्रामीण डेटा सेट बनाने में मदद करता है।

Ques: Which country did the UAE make its first central bank digital currency (CBDC) payment to?

यूएई ने अपनी पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) भुगतान किस देश को की?

- A) India / भारत
- B) China / चीन
- C) United States / अमेरिका
- D) Saudi Arabia / सऊदी अरब
- E) Japan / जापान

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The UAE completed its first central bank digital currency (CBDC) payment to China, marking a major milestone in global financial connectivity.
- यूएई ने चीन को अपनी पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) भुगतान पूरी की, जो वैश्विक वित्तीय जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- The transaction was executed via the newly launched Jisr platform, highlighting growing strategic cooperation between the two nations in digital finance and payment modernisation.
- यह लेन गए किए लॉन्च नए देन-Jisr प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया, जो डिजिटल वित्त और भुगतान आधुनिकीकरण में दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है।
- The Jisr platform, developed with participation from Emirati and Chinese banks, enables instant CBDC-based cross-border settlements.
- Jisr प्लेटफॉर्म, जिसे अमीराती और चीनी बैंकों की भागीदारी से विकसित किया गया है, तुरंत CBDC-आधारित सीमाहै। करता प्रदान सुविधा की भुगतान पार-

- More central banks are expected to join the network as it expands in 2026.
- जैसे नेटवर्क यह जैसे-2026 में विस्तारित होगा, और केंद्रीय बैंक इसमें शामिल होने की संभावना है।

Ques: How much dividend did state-owned GIC Re pay to the Government of India for FY24-25?

राज्य वाली स्वामित्व-GIC Re ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को कितना लाभांश दिया?

- A) Rs 750 crore / 750 करोड़ रुपये
- B) Rs 1,445 crore / 1,445 करोड़ रुपये
- C) Rs 2,100 crore / 2,100 करोड़ रुपये
- D) Rs 6,701 crore / 6,701 करोड़ रुपये
- E) Rs 10 crore / 10 करोड़ रुपये

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- State-owned GIC Re paid Rs 1,445 crore as dividend to the Government of India for FY24-25.
- राज्य वाली स्वामित्व-GIC Re ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को 1,445 करोड़ रुपये का लाभांश दिया।
- The government holds an 85.50% stake in the listed reinsurance company.
- सरकार की सूचीबद्ध पुनर्बीमा कंपनी में 85.50% हिस्सेदारी है।
- GIC Re recorded a profit of Rs 6,701.36 crore in FY25 and declared a final dividend of Rs 10 per equity share.
- GIC Re ने FY25 में 6,701.36 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभ दर्ज किया और प्रति इक्विटी शेयर 10 रुपये का अंतिम लाभांश घोषित किया।
- GIC Re employees have the highest per capita profit in India, with a workforce of fewer than 500 employees.
- 500 से कम कर्मचारियों के साथ, GIC Re के कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति लाभ देश में सबसे अधिक है।

About GIC Re :

- Established : 1972
- HQ : Mumbai
- CMD : Ramaswamy Narayanan

Ques: Which company received in-principle approval from SEBI to set up a Mutual Fund business?

किस कंपनी को म्यूचुअल फंड व्यवसाय स्थापित करने के लिए SEBI से इन प्रिंसिपल-मिला अनुमोदन?

- A) HDFC Asset Management / एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट
- B) Master Capital Services Limited / मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड
- C) SBI Mutual Fund / एसबीआई म्यूचुअल फंड
- D) ICICI Prudential AMC / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी
- E) Nippon India Mutual Fund / निप्पोन इंडिया म्यूचुअल फंड

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Master Capital Services Limited, a wholly-owned subsidiary of Master Trust, received in-principle approval from SEBI to set up a Mutual Fund (MF) business.
- मास्टर ट्रस्ट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड को म्यूचुअल फंड (MF) व्यवसाय स्थापित करने के लिए SEBI से इनमिला। अनुमोदन प्रिंसिपल-
- After this approval, the company can proceed with regulatory processes to establish an Asset Management Company (AMC) and launch mutual fund schemes, subject to SEBI's final approval.
- इस अनुमोदन के बाद, कंपनी SEBI की अंतिम स्वीकृति के अधीन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) स्थापित करने और म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने की नियामक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा सकती है।

**Ques: Who has been appointed as the Whole-Time Member (WTM) of SEBI?
किसे SEBI का होल) मेंबर टाइम-WTM) नियुक्त किया गया है?**

- A) Ashwani Bhatia / अश्वनी भाटिया
- B) Sandhip Pradhan / संधिप प्रधान
- C) Amarjeet Singh / अमरजीत सिंह
- D) Kamlesh Chandra Varshney / कमलेश चंद्र वर्शेई
- E) Rajesh Kumar / राजेश कुमार

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Sandhip Pradhan has been appointed as the Whole-Time Member (WTM) of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) for a term of three years.
- संधिप प्रधान को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) का होल मेंबर टाइम-WTM) तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है।
- He replaces Ashwani Bhatia in the role.
- उन्होंने अश्वनी भाटिया की जगह ली है।
- Currently, SEBI has two other Whole-Time Members — Amarjeet Singh and Kamlesh Chandra Varshney.
- वर्तमान में, SEBI के पास दो अन्य होल हैं मेंबर टाइम— अमरजीत सिंह और कमलेश चंद्र वर्शेई।

Ques: TIPS, with which RBI is linking UPI, is an instant payment system operated by which region?

TIPS, जिसके साथ RBI UPI को interlink कर रहा है, किस क्षेत्र द्वारा संचालित instant payment system है?

- A) ASEAN
- B) Eurozone
- C) SAARC
- D) BIMSTEC
- E) BRICS

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) is operated by the Eurosystem, which includes the European Central Bank (ECB) and central banks of Eurozone countries.
 - TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) यूरोसिस्टम द्वारा संचालित है, जिसमें यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) और यूरोज़ोन देशों के केंद्रीय बैंक शामिल हैं।
 - RBI has started linking India's UPI with TIPS to facilitate faster, seamless, and cost-effective cross-border remittances.
 - RBI ने भारत के UPI को TIPS से जोड़ना शुरू किया है ताकि cross-border remittances तेज, आसान और किफायती हों।
 - NIPL (NPCI International Payments Ltd) will partner with RBI to operationalise this integration.
 - NIPL (NPCI International Payments Ltd) RBI के साथ मिलकर इस interlinking को लागू करेगा।
 - Users in both India and the Eurozone are expected to directly benefit from this linkage.
 - भारत और यूरोज़ोन दोनों के उपयोगकर्ताओं को इस लिंक से सीधे लाभ मिलेगा।
-

Ques: From which month will AMFI start publishing separate data on Choti SIPs (₹250 SIPs)?

AMFI किस महीने से छोटी SIPs (₹250 SIPs) पर अलग डेटा प्रकाशित करना शुरू करेगा?

- A) December 2025
- B) January 2026
- C) February 2026
- D) March 2026
- E) April 2026

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Association of Mutual Funds in India (AMFI) will start publishing separate data on Choti SIPs (₹250 SIPs) from January 2026, after Registrar & Transfer Agents (RTAs) complete the required system modifications.
- भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन (AMFI) जनवरी 2026 से छोटी SIPs (₹250 SIPs) पर अलग डेटा प्रकाशित करना शुरू करेगा, जब रजिस्टार एवं ट्रांसफर एजेंट (RTAs) आवश्यक सिस्टम संशोधन पूरा कर लेंगे।
- SEBI reduced the minimum SIP amount to ₹250 to boost retail participation, but this is not allowed in debt, high-risk sectoral/thematic, small-cap, and mid-cap schemes.
- SEBI ने खुदरा भागीदारी बढ़ाने के लिए न्यूनतम SIP राशि ₹250 कर दी, लेकिन यह डेट, उच्च जोखिम वाले सेक्टरल/थीमैटिक, स्मॉल-कैप और मिड-कैप योजनाओं में अनुमति नहीं है।
- Due to high transaction costs, Choti SIP payments are allowed only through NACH or UPI AutoPay modes.
- उच्च लेन-देन लागत के कारण, छोटी SIP भुगतान केवल NACH या UPI AutoPay मोड के माध्यम से ही संभव है।
- RTAs must track only the first three Choti SIPs per investor (via PAN) eligible for subsidised transaction costs; additional SIPs will not receive subsidies.
- RTAs को प्रत्येक निवेशक PAN के माध्यम से (के केवल पहले तीन योग्य छोटी SIPs को सब्सिडी वाले लेन-देन खर्च के लिए ट्रैक करना चाहिए; अतिरिक्त SIPs को सब्सिडी नहीं मिलेगी।

About Association of Mutual Funds in India (AMFI)

- Established : 1995
- HQ : Mumbai
- CEO : Chalasani Venkat Nageswar

Ques: Which financial entity plans to request RBI to allow smaller urban cooperative banks to offer digital banking services?

कौन सी वित्तीय संस्था आरबीआई से छोटे शहरी सहकारी बैंकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति मांगने की योजना बना रही है?

- A) NABARD / नाबार्ड
- B) National Urban Co-operative Financial and Development Corporation (NUCFDC) / राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम
- C) SIDBI / लघु उद्योग विकास बैंक

D) RBI / भारतीय रिज़र्व बैंक

E) PFRDA / पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The National Urban Co-operative Financial and Development Corporation (NUCFDC) plans to approach the RBI to allow smaller urban cooperative banks (UCBs) with net worth below ₹50 crore to provide digital banking services such as internet banking, mobile banking, and UPI.
- राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (NUCFDC) आरबीआई से छोटे शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को ₹50 करोड़ से कम नेट वर्थ वाले बैंक के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति देने की योजना बना रहा है।
- Currently, only UCBs with net worth above ₹50 crore can offer digital banking, leaving over half of the 1,462 UCBs—holding ₹5.5 trillion in deposits—unable to provide these services.
- वर्तमान में, केवल ₹50 करोड़ से अधिक नेट वर्थ वाले UCBs ही डिजिटल बैंकिंग प्रदान कर सकते हैं, जिससे 1,462 UCBs में से आधे से अधिक, जिनके पास ₹5.5 ट्रिलियन की जमा राशि है, ये सेवाएँ नहीं दे पा रहे हैं।
- NUCFDC, a mid-layer NBFC since February 2024, is developing a central digital stack for UCBs, including IT infrastructure, applications, cybersecurity, manpower, and maintenance.
- फरवरी 2024 से मध्यम-स्तरीय NBFC के रूप में NUCFDC UCBs के लिए IT इन्फ्रास्ट्रक्चर, एप्लिकेशन, साइबर सुरक्षा, मानव संसाधन और रखरखाव सहित केंद्रीय डिजिटल स्टैक विकसित कर रहा है।
- In March 2024, Union Minister for Cooperation Amit Shah inaugurated NUCFDC, an umbrella organisation for urban cooperative banks.
- मार्च 2024 में, सहयोग मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए छत्र संगठन NUCFDC का उद्घाटन किया।

Ques: According to IRDAI, by what percentage did health insurance claims rise in FY25?

IRDAI के अनुसार FY25 में स्वास्थ्य बीमा दावे कितने प्रतिशत बढ़े?

- A) 12.88%
- B) 18.5%
- C) 21.18%
- D) 25.40%
- E) 30.12%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- IRDAI reported that health insurance claims surged by 21.18% in FY25, even as the settlement of claims lagged.
- IRDAI के अनुसार FY25 में स्वास्थ्य बीमा दावे 21.18% बढ़े, जबकि सेटलमेंट की गति पीछे रह गई।
- Insurers settled 3.26 crore health claims and paid ₹94,247 crore in FY25.
- बीमा कंपनियों ने FY25 में 3.26 करोड़ दावे निपटाए और ₹94,247 करोड़ का भुगतान किया।
- The total amount settled increased by only 12.88%, showing a clear mismatch between claims filed and claims paid.
- कुल सेटलमेंट राशि केवल 12.88% बढ़ी, जिससे दावे और भुगतान के बीच बड़ा अंतर दिखा।
- Rising healthcare costs, increased hospitalisation, and inefficiencies in systems are contributing factors.
- स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत, अस्पताल में भर्ती बढ़ने और सिस्टम की अक्षमताएं इसके मुख्य कारण हैं।
- ICR (Incurred Claims Ratio) lowest for standalone health insurers — signalling pressure on profitability.
- ICR (इनकर्ड क्लेम्स रेशियो) रहा कम सबसे लिए के इंश्योरर्स हेल्थ स्टैंडअलोन (— लाभप्रदता पर दबाव दिखाता है।
- FY25 premium collected: ₹1.18 lakh crore, up from ₹1.08 lakh crore in FY24.
- FY25 में प्रीमियम संग्रह : ₹1.18 लाख करोड़, FY24 के ₹1.08 लाख करोड़ से अधिक।
- Public sector insurers showed 103% ICR, private sector at 88.71%.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं का ICR 103%, निजी क्षेत्र का 88.71% रहा।
- The rise in claims is due to higher medical inflation, increased healthcare

costs, and greater use of insurance.

- इसका कारण मेडिकल इंप्लेशन, इलाज की बढ़ती लागत और स्वास्थ्य बीमा उपयोग में वृद्धि है।

Ques: PayGlocal has received RBI's final approval to operate as which category of Payment Aggregator?

PayGlocal को RBI से किस श्रेणी के पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की अंतिम मंजूरी मिली है?

- A) PA – Domestic / PA – घरेलू
- B) PA – Cards Only / PA – केवल कार्ड
- C) PA – Cross Border – Inward & Outward / PA – क्रॉस बॉर्डर – इनवर्ड और आउटवर्ड
- D) PA – Wallet Based / PA – वॉलेट आधारित
- E) PA – UPI Only / PA – केवल UPI

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- PayGlocal has received final approval from the Reserve Bank of India (RBI) to operate as a Payment Aggregator – Cross Border – Inward & Outward (PA-CB-I&O).
- PayGlocal को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर – क्रॉस बॉर्डर – इनवर्ड और आउटवर्ड (PA-CB-I&O) के रूप में काम करने की अंतिम मंजूरी मिली है।
- This approval allows PayGlocal to process cross-border digital transactions in both directions — money coming into India and payments going out of India.
- इस मंजूरी से PayGlocal क्रॉसडिजि बॉर्डर-टल लेनदेन से भारत और वाले आने में भारत) सकेगा। कर प्रोसेस को दोनों (भुगतान वाले जाने बाहर
- It strengthens India's fintech ecosystem by enabling secure, compliant, and faster global payments.
- यह मंजूरी भारत के फिनटेक सेक्टर को सुरक्षित, नियमतेज और संगत- वैश्विक भुगतान सुविधाएँ देकर मजबूत करती है।
- PayGlocal works with banks and regulated entities to support global merchant payments.
- PayGlocal बैंक और विनियमित संस्थाओं के साथ मिलकर वैश्विक व्यापारी भुगतानों का

समर्थन करता है।

- India is rapidly expanding its cross-border digital payments footprint, and this approval adds another strong player to the ecosystem.
- भारत तेजी से अपने क्रॉसहै रहा कर विस्तार का नेटवर्क भुगतान डिजिटल बॉर्डर-, और यह मंजूरी इस इकोसिस्टम में एक और मजबूत खिलाड़ी जोड़ती है।

Ques: NCDEX is preparing to acquire a stake in the upcoming CSEDEX exchange of which country?

NCDEX किस देश के नए CSEDEX एक्सचेंज में हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी कर रहा है?

- A) Bangladesh / बांग्लादेश
- B) Sri Lanka / श्रीलंका
- C) Nepal / नेपाल
- D) Myanmar / म्यांमार
- E) Thailand / थाईलैंड

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- NCDEX (National Commodity & Derivatives Exchange, India) is preparing to acquire a 20% stake in CSEDEX, a new commodities and financial derivatives exchange being set up in Sri Lanka.
- भारत का नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) श्रीलंका के नए कमोडिटी और वित्तीय डेरिवेटिव्स एक्सचेंज CSEDEX में 20% हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी कर रहा है।
- The investment value is 70 million Sri Lankan rupees (~₹24 crore).
- यह निवेश 70 मिलियन श्रीलंकाई रुपये)~₹24 करोड़होगा। का (
- The move aims to expand NCDEX's regional presence and strengthen international commodity market cooperation.
- इससे NCDEX अपने क्षेत्रीय विस्तार और अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी सहयोग को मजबूत करेगा।
- The collaboration is based on an MoU signed earlier in 2025, with NCDEX supporting the project under a build–operate–transfer (BOT) model.
- यह साझेदारी 2025 की शुरुआत में हुए MoU पर आधारित है, और NCDEX इसे Build–Operate–Transfer (BOT) मॉडल पर सहयोग देगा।
- NCDEX will assist Sri Lanka in technical architecture, product design, training,

and regulatory frameworks.

- NCDEX तकनीकी ढांचा, उत्पाद डिजाइन, प्रशिक्षण और नियम की श्रीलंका में प्रक्रियाओं-करेगा। मदद
- Sri Lanka currently has no commodity or financial derivatives exchange.
- श्रीलंका में वर्तमान में कोई क्मोडिटी या वित्तीय डेरिवेटिव्स एक्सचेंज नहीं है।
- NCDEX Background: Established in 2003; regulated by SEBI; India's major agricultural derivatives exchange. It recently saw volume decline after suspension of major agri contracts.
- NCDEX पृष्ठभूमि :2003 में स्थापित; SEBI द्वारा विनियमित; भारत का प्रमुख कृषि डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। प्रमुख कृषि कॉन्ट्रैक्ट्स निलंबित होने के बाद हाल में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट देखी गई।

Ques: As per the proposed Insurance Laws (Amendment) Bill, what will be the new FDI limit in India's insurance sector?

प्रस्तावित इंश्योरेंस लॉज़ अनुसार के विधेयक (संशोधन), भारत के बीमा क्षेत्र में नई FDI सीमा क्या होगी?

- A) 74%
- B) 90%
- C) 100%
- D) 49%
- E) 85%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The government plans to introduce the Insurance Laws (Amendment) Bill in the Winter Session of Parliament to raise the FDI limit from 74% to 100% in the insurance sector.
- सरकार सर्दियों के सत्र में इंश्योरेंस लॉज़ करेगी पेश विधेयक (संशोधन), जिसके तहत बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है।
- The move aims to boost insurance penetration, attract foreign investment, and improve ease of doing business.
- इसका उद्देश्य बीमा पहुंच बढ़ाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना है।

- The Bill may also empower IRDAI to fix lower entry capital (minimum ₹50 crore) for insurers serving under-developed segments.
- यह विधेयक IRDAI को कम एंट्री कैपिटल (न्यूनतम) ₹50 करोड़ देगा भी शक्ति की करने तय (, खासकर पिछड़े क्षेत्रों में सेवाएँ देने वाले बीमाकर्ताओं के लिए।
- Requirement of Net Owned Funds (NOF) for foreign re-insurers may be reduced from ₹5,000 crore to ₹1,000 crore.
- विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों के लिए नेट ओन्ड फंड (NOF) की आवश्यकता ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ करने का प्रस्ताव है।
- The Bill also includes provisions for composite licences, allowing insurers to sell life + health + general insurance under a single licence.
- बिल में कॉम्पोज़िट लाइसेंस की व्यवस्था भी शामिल है, जिससे बीमा कंपनियाँ लाइफ + सकेंगी। कर प्रदान तहत के लाइसेंस ही एक इंश्योरेंस जनरल + हेल्थ
- India's insurance sector is projected to grow at 7.1% annually over the next five years.
- भारत का बीमा क्षेत्र अगले पाँच वर्षों में 7.1% वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान है।

Ques: Which Indian fintech firm recently received RBI approval to operate as a full-service Payment Aggregator?

कौन सी भारतीय फिनटेक कंपनी ने हाल ही में RBI से पूर्ण-सेवा पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी प्राप्त की?

- A) Razorpay / रेज़रपे
- B) PayGlocal / पेग्लोकल
- C) Paytm / पेटीएम
- D) PhonePe / फोनपे
- E) Easbuzz / ईज़बज़

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Easbuzz, an Indian fintech company, received RBI approval under the Payment and Settlement Systems (PSS) Act, 2007 to operate as a full-service Payment Aggregator (PA).

- Easebuzz, एक भारतीय फिनटेक कंपनी, को पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स (PSS) एक्ट, 2007 के तहत पूर्ण-सेवा पेमेंट एग्रीगेटर (PA) के रूप में काम करने की RBI मंजूरी मिली।
- With this, Easebuzz became the third payment fintech in India to hold all three PA licences.
- इसके साथ ही Easebuzz भारत की तीसरी पेमेंट फिनटेक बन गई, जिसे सभी तीन PA लाइसेंस प्राप्त हैं।
- The approval allows Easebuzz to support digital payments across online, offline, and cross-border platforms.
- यह मंजूरी Easebuzz को ऑनलाइन, ऑफलाइन और क्रॉस-बॉर्डर प्लेटफॉर्म पर डिजिटल भुगतान का समर्थन करने की सुविधा देती है।
- Easebuzz offers a full-stack payment suite, including online payments, Point of Sale (PoS) in-person transactions, UPI sandbox acceptance, and cross-border inward & outward transactions.
- Easebuzz ऑनलाइन भुगतान, प्वाइंट ऑफ़ सेल (PoS) इन-पर्सन ट्रांज़ैक्शन, UPI साउंडबॉक्स स्वीकृति और क्रॉस-बॉर्डर इनवर्ड व आउटवर्ड लेनदेन सहित पूर्ण पेमेंट सुइट प्रदान करता है।

Ques: To which fiscal year will India switch its GDP national accounts base year as announced by MoSPI?

मोसपी द्वारा घोषित अनुसार भारत अपने GDP राष्ट्रीय खातों का आधार वर्ष किस वित्तीय वर्ष में बदलने जा रहा है?

- A) FY 2011-12
- B) FY 2015-16
- C) FY 2022-23
- D) FY 2023-24
- E) FY 2004-05

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) will switch the base year for India's GDP national accounts from FY 2011-12 to FY 2022-23.
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) भारत के GDP राष्ट्रीय खातों का आधार वर्ष FY 2011-12 से FY 2022-23 में बदल देगा।

- The new series is scheduled to be released on 27 February 2026.
- नई श्रृंखला 27 फरवरी 2026 को जारी की जाने वाली है।
- A base year acts as a reference year for calculating growth, prices, and national income.
- आधार वर्ष वृद्धि, मूल्य और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए संदर्भ वर्ष के रूप में कार्य करता है।
- The last major revision of the base year was in 2015, when it changed from FY 2004-05 to FY 2011-12.
- आधार वर्ष का पिछला प्रमुख संशोधन 2015 में हुआ था, जब इसे FY 2004-05 से FY 2011-12 में बदल दिया गया था.
- A high-level Advisory Committee on National Account Statistics (ACNAS) chaired by Prof. B.N. Goldar has been formed to oversee this revision.
- इस संशोधन की निगरानी के लिए प्रोफेसर B.N. गोलदार की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय सलाहकार समिति ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स (ACNAS) का गठन किया गया है।

Ques: Who has been appointed as the Part-Time Chairperson of Jana Small Finance Bank (Jana SFB)?

जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक (Jana SFB) के पार्ट-टाइम चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) R. Ramaseshan / आर .रामशेशन
- B) Shikha Sharma / शिखा शर्मा
- C) Chitra Talwar / चित्रा तलवार
- D) Usha Anand Subramanian / उषा आनंद सुब्रमण्यम
- E) Anil Kumar Singh / अनिल कुमार सिंह

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Chitra Talwar has been appointed as the Part-Time Chairperson of Jana Small Finance Bank Limited for a term of 2 years, till 30 January 2028.
- चित्रा तलवार को जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का पार्ट-टाइम चेयरपर्सन 2 वर्ष के कार्यकाल) 30 जनवरी 2028 तक (के लिए नियुक्त किया गया है।
- She replaces R. Ramaseshan in this role.

- उन्होंने आर .रामसेशन का स्थान लिया है।
- She has been serving as an Independent Director on the bank's board since January 2020.
- वह जनवरी 2020 से बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं।

About Jana Small Finance Bank :

- Established : 2018
- HQ : Bangalore, Karnataka
- CEO & MD : Ajay Kanwal
- Tagline : Paise Ki Kadar

Ques: What is the total approved borrowing limit for India's first maritime NBFC, Sagarmala Finance Corporation Limited (SMFCL)?

भारत की पहली समुद्री गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी, सागर्माला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (SMFCL) के लिए कुल अनुमोदित उधारी सीमा क्या है?

- A) Rs 5,000 crore
- B) Rs 10,000 crore
- C) Rs 15,000 crore
- D) Rs 25,000 crore
- E) Rs 30,000 crore

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Sagarmala Finance Corporation Limited (SMFCL), India's first maritime NBFC, has approved an overall borrowing limit of Rs 25,000 crore, with Rs 8,000 crore earmarked for FY25 to start operations.
- भारत की पहली समुद्री NBFC, सागर्माला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (SMFCL) ने कुल उधारी सीमा ₹25,000 करोड़ अनुमोदित की है, जिसमें FY25 के लिए ₹8,000 करोड़ निर्धारित हैं।
- To raise these funds, SMFCL will mobilise resources through banks, financial institutions, and bond issuances as per its resource mobilisation plan.
- इन फंड्स को जुटाने के लिए SMFCL अपनी संसाधन जुटाने की योजना के अनुसार बैंकों,

वित्तीय संस्थाओं और बॉन्ड इश्यू के माध्यम से धन जुटाएगी।

- SMFCL, formerly Sagarmala Development Company Limited, is the first maritime sector-specific NBFC in India.
- SMFCL, जिसे पहले सागर्माला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड कहा जाता था, भारत की पहली समुद्री क्षेत्र-विशेष NBFC है।
- The corporation was formally registered with the Reserve Bank of India on 19, 2025 and functions under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.
- यह कॉरपोरेशन 19, 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक में औपचारिक रूप से पंजीकृत हुई और यह बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।

Ques: Which country recently unveiled an official currency symbol for its national currency, the Rial?

किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा रियाल के लिए आधिकारिक मुद्रा चिन्ह जारी किया है?

- A) Qatar / कतर
- B) Bahrain / बहरीन
- C) Oman / ओमान
- D) Kuwait / कुवैत
- E) Saudi Arabia / सऊदी अरब

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Central Bank of Oman (CBO) officially introduced a new symbol for the Omani Rial to standardize its use across financial, commercial, and digital platforms.
- ओमान के केंद्रीय बैंक (CBO) ने ओमानी रियाल के लिए नया आधिकारिक चिन्ह जारी किया ताकि इसे वित्तीय, वाणिज्यिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समान रूप से उपयोग किया जा सके।
- The design reflects Oman's rich cultural heritage and growing economic maturity.
- इसका डिजाइन ओमान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक परिपक्वता को दर्शाता है।
- With this, Oman joins the list of countries with a unique currency symbol,

similar to India (₹), UK (£), and Japan (¥).

- इसके साथ ही ओमान उन देशों की सूची में शामिल हो गया जिनकी विशिष्ट मुद्रा का चिन्ह है, जैसे भारत (₹), यूके (£), और जापान (¥)।

Ques: What was the sales growth of listed private non-financial companies in Q2 FY2025-26?

Q2 FY2025-26 में सूचीबद्ध निजी गैररही कितनी वृद्धि बिक्री की कंपनियों वित्तीय-?

- A) 5.4%
- B) 5.5%
- C) 7%
- D) 8%
- E) 10%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Sales growth of listed private non-financial companies rose to 8% in Q2 FY2025-26, up from 5.5% in the previous quarter.
- सूचीबद्ध निजी गैर वृद्धि बिक्री की कंपनियों वित्तीय-Q2 FY2025-26 में 8% रही, जो पिछले तिमाही के 5.5% से बढ़ी।
- 1,775 listed private manufacturing companies saw 8.5% year-on-year growth in Q2, driven by automobiles, food products, electrical machinery, and chemicals sectors.
- 1,775 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों ने Q2 में 8.5% सालकी दर्ज वृद्धि साल-दर-, जो ऑटोमोबाइल, खाद्य उत्पाद, विद्युत मशीनरी और रसायन क्षेत्रों द्वारा प्रेरित थी।
- IT companies' sales grew 7.8% (y-o-y) in Q2, up from 6.0% in the previous quarter.
- आईटी कंपनियों की बिक्री Q2 में 7.8% (साल(साल-दर- बढ़ी, जो पिछले तिमाही के 6.0% से अधिक थी।
- Non-IT services companies recorded 10.6% sales growth in Q2, up from 7.5% in the previous quarter.
- गैर ने कंपनियों सेवा आईटी-Q2 में 10.6% बिक्री वृद्धि दर्ज की, जो पिछले तिमाही के 7.5% से अधिक थी।

Ques: Who has been appointed as the Executive Director of Canara Bank for a tenure of 3 years?

कनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 साल के कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Shri. Rajesh Kumar / श्री राजेश कुमार
- B) Shri. Sunil Kumar Chugh / श्री सुनील कुमार चुग
- C) Shri. Anil Kumar / श्री अनिल कुमार
- D) Shri. Pankaj Singh / श्री पंकज सिंह
- E) Shri. Ramesh Gupta / श्री रमेश गुप्ता

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Shri. Sunil Kumar Chugh has been appointed as the Executive Director of Canara Bank for a tenure of 3 years.
- श्री सुनील कुमार चुग को कनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है।
- Prior to this appointment, he was serving as the Chief General Manager at Punjab National Bank.
- इस नियुक्ति से पहले वह पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य महाप्रबंधक (Chief General Manager) के पद पर कार्यरत थे।

About Canara Bank:

- Established : 1906
 - HQ : Bangalore, Karnataka
 - MD & CEO : K. Satyanarayana Raju
 - Tagline : Together we can
-

Ques: According to an SBI report, implementing four labour codes in India may create how many jobs and boost consumption by how much?

SBI की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में चार श्रम संहिताओं को लागू करने से कितनी नौकरियाँ सृजित हो सकती हैं और उपभोग में कितनी वृद्धि हो सकती है?

- A) 50 lakh jobs & ₹50,000 crore
- B) 77 lakh jobs & ₹75,000 crore
- C) 1 crore jobs & ₹1 lakh crore
- D) 25 lakh jobs & ₹30,000 crore
- E) 60 lakh jobs & ₹60,000 crore

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- SBI report states that implementing the four labour codes—Code on Wages (2019), Industrial Relations Code (2020), Code on Social Security (2020), and Occupational Safety, Health & Working Conditions Code (2020)—may create 77 lakh jobs and boost consumption by ₹75,000 crore.
- SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि चार श्रम संहिताओं को लागू करने से 77 लाख नौकरियाँ सृजित हो सकती हैं और उपभोग में ₹75,000 करोड़ की वृद्धि हो सकती है।
- The codes are expected to reduce unemployment from current 3.2% to a range of 1.9%–2.9% depending on scenario.
- इन संहिताओं से वर्तमान 3.2% बेरोजगारी को 1.9%–2.9% तक घटाने की संभावना है।
- All workers will become eligible for minimum wages under the Code on Wages, potentially increasing daily income by ₹95, leading to higher consumption after savings.
- वेतन संहिता के तहत सभी श्रमिक न्यूनतम वेतन के पात्र होंगे, जिससे दैनिक आय ₹95 बढ़ सकती है और बचत के बाद उपभोग में वृद्धि होगी।
- Formalisation of workforce expected to rise by 15.1%, reaching 75.5% of workforce in formal sector.
- कार्यबल का औपचारिकरण 15.1% बढ़ने की संभावना है, जिससे औपचारिक क्षेत्र में कार्यबल 75.5% तक पहुँच जाएगा।
- 44 crore workers in unorganised sector; 31 crore registered on e-Shram portal.
- 44 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं; 31 करोड़ e-Shram पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

Ques: Which bank signed a strategic partnership with Hub71 and the UAE–India CEPA Council to support Indian start-ups globally?

कौन सा बैंक हब71 और UAE–India CEPA काउंसिल के साथ भारतीय स्टार्टअप्स का वैश्विक स्तर पर समर्थन करने के लिए रणनीतिक साझेदारी में शामिल हुआ?

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) First Abu Dhabi Bank (FAB) / फर्स्ट अबू धाबी बैंक
- C) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- D) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- E) Axis Bank / एक्सिस बैंक

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- First Abu Dhabi Bank (FAB) and Hub71, Abu Dhabi's global tech ecosystem, signed strategic partnerships with the UAE–India Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Council to accelerate cross-border entrepreneurship and support Indian start-ups to scale globally through the UAE.
- फर्स्ट अबू धाबी बैंक (FAB) और हब71, अबू धाबी की वैश्विक टेक्नोलॉजी ईकोसिस्टम, ने UAE–India CEPA काउंसिल के साथ रणनीतिक साझेदारी की, जिससे सीमा पार उद्यमिता को बढ़ावा मिले और भारतीय स्टार्टअप्स को UAE के माध्यम से वैश्विक स्तर पर विस्तार करने का समर्थन मिले।
- From a pool of start-ups, 20 outstanding companies were selected to showcase Indian innovation in New Delhi on November 25, with five chosen to expand globally using the UAE as their launchpad.
- स्टार्टअप्स के पूल में से 20 उत्कृष्ट कंपनियों को 25 नवंबर को नई दिल्ली में भारतीय नवाचार प्रदर्शित करने के लिए चुना गया, जिनमें से पांच को UAE को लॉन्चपैड बनाकर वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिए चयनित किया जाएगा।
- The agreement was signed at the Abu Dhabi Investment Forum (ADIF) in Mumbai.
- यह समझौता मुंबई में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फोरम (ADIF) में हस्ताक्षरित किया गया।

Ques: What factors drove India's economic growth in October 2025 despite global challenges?

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अक्टूबर 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि को कौन से कौन-कारक बढ़ावा दे रहे थे?

- A) GST rate rationalisation & festival spending / GST दरों का समायोजन और त्योहारी खर्च
- B) High exports & low imports / उच्च निर्यात और कम आयात
- C) Increased foreign direct investment / बढ़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
- D) Decline in credit growth / ऋण वृद्धि में कमी
- E) Reduction in government spending / सरकारी खर्च में कमी

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- India's economic growth in October 2025 was driven by GST rate rationalisation and higher consumer spending during festivals.
- अक्टूबर 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि GST दरों के समायोजन और त्योहारी मौसम में बढ़े उपभोक्ता खर्च से प्रेरित थी।
- Reserve Bank of India (RBI) noted improvement in manufacturing and services sectors, with strong macroeconomic frameworks supporting the economy.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में सुधार और मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक ढांचे की भूमिका का उल्लेख किया, जिसने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया।
- GST collections increased compared to the previous month, indicating a rise in consumer demand.
- पिछले महीने की तुलना में GST संग्रह में वृद्धि हुई, जो उपभोक्ता मांग में वृद्धि को दर्शाती है।
- Fiscal, monetary, and regulatory measures are expected to create a virtuous cycle of higher private investment, productivity, and growth.
- वित्तीय, मौद्रिक और नियामक उपाय उच्च निजी निवेश, उत्पादकता और वृद्धि का एक सकारात्मक चक्र उत्पन्न करने की उम्मीद है।
- Merchandise trade deficit reached an all-time high due to surging imports (gold & silver) despite export contraction.
- निर्यात में गिरावट के बावजूद आयात घाटा व्यापार वस्त्र से बढ़ोतरी में (चांदी और सोना) गया। पहुंच पर स्तर उच्चतम के तक अब

Ques: Which securities did SEBI propose to exclude from BSDA portfolio value calculation?

SEBI ने BSDA पोर्टफोलियो मूल्यांकन से किन प्रतिभूतियों को बाहर करने का प्रस्ताव रखा?

- A) Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) bonds / ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल (ZCZP) बॉन्ड
- B) Delisted securities / डीलिस्टेड प्रतिभूतियां
- C) Suspended securities / निलंबित प्रतिभूतियां
- D) Both A & B / दोनों A और B
- E) Government securities / सरकारी प्रतिभूतियां

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- SEBI proposed excluding Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) bonds and delisted securities from Basic Services Demat Account (BSDA) portfolio value calculation.
- SEBI ने BSDA पोर्टफोलियो मूल्यांकन से ZCZP बॉन्ड और डीलिस्टेड प्रतिभूतियों को बाहर करने का प्रस्ताव रखा।
- ZCZP bonds are non-transferable, non-tradable, and provide no monetary return, hence treated like social contribution, not investment.
- ZCZP बॉन्ड गैरहस्तांतरणीय-, गैरदेते नहीं लाभ मौद्रिक कोई और हैं योग्य व्यापार-, इसलिए इन्हें निवेश नहीं बल्कि सामाजिक योगदान माना जाता है।
- Delisted securities are proposed to be excluded similar to already-excluded suspended securities due to lack of price discovery and liquidity.
- डीलिस्टेड प्रतिभूतियों को निलंबित प्रतिभूतियों की तरह बाहर करने का प्रस्ताव है, क्योंकि इनमें मूल्य खोज और तरलता नहीं है।
- Illiquid securities will still be valued at last closing price. Reassessment of BSDA eligibility is proposed quarterly instead of varying billing cycles.
- तरल प्रतिभूतियों का मूल्य अंतिम बंद मूल्य पर रखा जाएगा। BSDA पात्रता का पुनर्मूल्यांकन तिमाही आधार पर प्रस्तावित है।
- SEBI suggests easier consent methods for investors preferring normal demat accounts.
- सामान्य डिमैट खाते चुनने वाले निवेशकों के लिए SEBI ने आसान सहमति चैनलों की सिफारिश की है।